twitter.com/divyadelhi facebook.com/divyadelhi infodivyadelhi@gmail.com Editor: Rajesh Chauhan

RNI No. DELHI/2013/54397

दिव्य दिल्ली

divyadelhi.com | रविवार, 24 अगस्त, 2025 | वर्ष: 12, अंक: 277, पृष्ठ: 08 | ₹ 05/- | दिल्ली से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र

भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा: पीएम मोदी

कार्यक्रम में शुभांशु शुक्ला के साथ गगनयान मिशन पर जाने वाले अन्य अंतरिक्ष यात्री भी मौजूद रहे

नई दिल्ली
राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में भारत मंडपम में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय अंतरिक्षयात्री शुभांशु शुक्ला के साथ गगनयान मिशन पर जाने वाले अन्य अंतरिक्षयात्री भी मौजूद रहे। साथ ही केंद्रीय विज्ञान और तकनीक मंत्री जितेंद्र सिंह और इसरो के चेयरमैन वी नारायणन भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने देशवासियों को दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की बधाई दी।

'अंतरिक्ष क्षेत्र में एक के बाद एक नई उपलब्धि हासिल कर रहा भारत'

प्रधानमंत्री ने कहा कि 'इस बार के अंतरिक्ष दिवस की थीम आर्यभट्ट से गगनयान तक है। इसमें अतीत का आत्मविश्वास भी है और भविष्य का संकल्प भी। आज हम देख रहे हैं कि इतने कम समय में ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हमारे युवाओं के बीच उत्साह और आकर्षण का विषय बन गया है। यह देश के लिए गौरव की बात है।' प्रधानमंत्री ने कहा कि 'अंतरिक्ष क्षेत्र में एक के बाद एक नई उपलब्धि हासिल करना, ये भारत और भारत के वैज्ञानिकों का स्वभाव बन गया है। दो साल पहले ही भारत ऐसा पहला देश बना था जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने का इतिहास रचा। हम उन देशों में भी शामिल हो गए हैं, जिन्होंने अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग की क्षमता हासिल कर ली है।'

आने वाले समय में अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा भारत

उन्होंने कहा कि 'शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तिरंगा फहराकर हर भारतीय को गर्व से भर दिया।

कम समय में भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की : प्रधानमंत्री

पीएम मोदी ने कहा कि दो वर्ष पूर्व भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना था। साथ ही, शुभांशु शुक्ला ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर तिरंगा फहराकर हर भारतीय को गर्व से भर दिया। प्रधानमंत्री ने इसे अविस्मरणीय क्षण बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज अंतरिक्ष क्षेत्र में बदलाव लाने वाली तकनीकों पर कार्य कर रहा है। इनमें सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी प्रगतियां शामिल हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि निकट भविष्य में भारत का गगनयान मिशन उड़ान भरेगा और देश का अपना अंतरिक्ष स्टेशन भी स्थापित होगा।

साल 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रहे: नारायणन

नई दिल्ली
राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष वी. नारायणन ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और दृष्टिकोण के आधार पर हम चंद्रयान-4 मिशन करने जा रहे हैं। हम एक शुक्र ग्रह ऑर्बिटर मिशन करने जा रहे हैं। हम साल 2035 तक एक स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं, जिसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कहा जाएगा और इसका पहला मॉड्यूल साल 2028 तक प्रक्षेपित किया जाएगा। नेशनल स्पेस डे के मौके पर भारत मंडपम में आयोजित

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वी नारायणन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक एनजीएल (नेक्स्ट जेनरेशन लॉन्चर) को भी मंजूरी दी है। साल 2040 तक भारत चाँद पर उतरेगा और सुरक्षित वापसी भी करेगा। इस प्रकार साल 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया के किसी भी अन्य अंतरिक्ष कार्यक्रम के बराबर होगा। इसरो अध्यक्ष वी. नारायणन ने कहा, "हमारी एक बड़ी उपलब्धि यह है कि हमने अपने एक 'गगनयात्री' को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा। इसके लिए फिर से प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करना होगा। यह उनका ही विचार था कि अपने रॉकेट से गगनयात्री को भेजने से पहले हमें उनमें से एक को आईएसएस भेजना चाहिए। उनकी दूरदृष्टि ने आज एक बड़ी सफलता दिलाई। शुभांशु शुक्ला आई एसएस गए और सुरक्षित लौट आए। इसरो अध्यक्ष वी. नारायणन ने कहा, कि 23 अगस्त 2023 एक ऐतिहासिक दिन था। भारत ने चंद्रयान-3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतारा।

भारत ने अपने हवाई क्षेत्र में पाकिस्तानी विमानों पर लगी पाबंदी 24 सितंबर तक बढ़ाई

नई दिल्ली
भारत ने अपने हवाई क्षेत्र में पाकिस्तानी विमानों पर लगी पाबंदी एक बार फिर 24 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। पड़ोसी देश ने भी अपने हवाई क्षेत्र को भारतीय विमानों पर पाबंदी की अवधि को बढ़ा कर 24 सितंबर कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को दी जानकारी में बताया कि दोनों देशों ने हवाई क्षेत्र को बंद करने की अवधि बढ़ाने के लिए अलग-अलग नोटिस टू एयरमेन (नोटम) जारी किए हैं। 22 अगस्त को जारी नोटिस के मुताबिक भारतीय हवाई क्षेत्र पाकिस्तान में पंजीकृत विमानों और पाकिस्तानी एयरलाइनों/संचालकों द्वारा संचालित/स्वामित्व वाले या पट्टे पर लिए गए विमानों, जिनमें सैन्य उड़ानें भी शामिल हैं, उसके लिए उपलब्ध नहीं होगा। हवाई क्षेत्र 23 सितंबर को 23.59 बजे तक बंद रहेगा, जो 24 सितंबर को 0530 बजे तक होगा। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद पाकिस्तानी एयरलाइंस और ऑपरेटरों द्वारा संचालित, स्वामित्व वाले या पट्टे पर लिए गए विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था, जिसमें सैन्य उड़ानें भी शामिल थीं।

धर्मस्थल मंदिर को बदनाम करने की हो रही साजिश: अन्नामलाई

चेन्नई
तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में कर्नाटक के धर्मस्थल मामले के पीछे एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 'एक नकाबपोश व्यक्ति ने कर्नाटक की पूरी सरकारी मशीनरी को घुमाकर रख दिया है और उसका एकमात्र उद्देश्य सनातन धर्म के स्तंभों में से एक धर्मस्थल मंदिर को बदनाम करना है। इस मामले के पीछे गहरी साजिश है।' अन्नामलाई ने कहा कि 'कर्नाटक सरकार ने एक नकाबपोश व्यक्ति के आधारहीन दावों को सत्यता दे दी है, जबकि उसके दावों का कोई सबूत भी नहीं है। एसआईटी बनाकर 13 जगहों पर खुदाई भी शुरू कर दी गई। हालांकि खुदाई वाली जगह से सिर्फ एक कंकाल मिला है और वो भी पुरुष का है।

एससीओ शिखर सम्मेलन में होगी मोदी-ओली की मुलाकात

नई दिल्ली
चीन के तियांजिंग में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की वहां विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ होने वाली बैठक से इतर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली मुलाकात का समय तय हो गया है। दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच यह तीसरी मुलाकात होगी। 31 अगस्त से शुरू होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री के साथ इस मुलाकात की जानकारी प्रधानमंत्री सचिवालय की तरफ से दी गई है। प्रधानमंत्री के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार विष्णु रिमाल ने कहा कि तियांजिंग में एक सितंबर को नेपाल और भारतीय प्रधानमंत्री के साथ बैठक से इतर यह मुलाकात होना तय हुआ है। एससीओ में भारत जहां मुख्य सदस्य देश के रूप में सहभागी होने जा रहा है वहीं नेपाल डायलॉग पार्टनर के रूप में पहली बार प्रधानमंत्री स्तर पर प्रतिनिधित्व होने वाला है। चीन में इस वर्ष एससीओ शिखर सम्मेलन को एससीओ प्लस के रूप में आयोजित कर रहा है जिसमें मुख्य सदस्य देशों के अलावा सभी पर्यवेक्षक देश और डायलॉग पार्टनर देशों को भी आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री ओली के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के लिए नेपाल के तरफ से आग्रह किया गया था।

तूफानों से जूझने की आदत है, नहीं डरती आसुरी शक्ति से: रेखा गुप्ता

नई दिल्ली
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को कहा कि उन्हें तूफानों से जूझने की आदत है और किसी भी आसुरी शक्ति से नहीं डरती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने अपनी भागदौड़, प्यार और आशीर्वाद देकर उन्हें शाक्तियों का अंबार बना दिया है। यह बातें मुख्यमंत्री ने शनिवार को श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के 99वें वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कही।

समारोह कॉलेज के श्रीधर आडिटोरियम में हुआ। मुख्यमंत्री

ने इस दौरान शिक्षकों और छात्रों से संवाद किया और सभी विजेताओं और प्रतिभागियों को ढेरों शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि एशिया के सर्वश्रेष्ठ कॉमर्स कॉलेज का यह गौरवशाली सफर हम सबके लिए गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेज जीवन की यादें सचमुच सुनहरी होती हैं। चाहे जीवन में हम कितनी भी ऊंचाइयां क्यों न छू लें, वे दिन हमेशा मन में ताजा रहते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा रही हूं, इसलिए आज यह वातावरण मुझे अपने ही पुराने दिनों में लौटा ले गया। उन्होंने आज के युवाओं से अपील है कि अपने जीवन का एक हिस्सा राष्ट्र के उत्थान के लिए जरूर समर्पित करें। उन्होंने सभी से मिलकर एक नई, बेहतर और सशक्त दिल्ली बनाने की अपील की है।

'पाक के मामले में कभी भी किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की'

नई दिल्ली
भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम कराने का दावा कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने आईना दिखाया। विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हमने पाकिस्तान के मामले में कभी भी किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। पाकिस्तान के साथ मध्यस्थता को लेकर भारत का रुख हमेशा स्पष्ट रहा है और आगे भी रहेगा।

एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष के मुद्दे पर हमने 1970 से लेकर अब तक 50 साल में कभी भी किसी की

मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। भारत में हमेशा से राष्ट्रीय सहमति रही है कि हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में मध्यस्थता स्वीकार नहीं करते हैं। जब व्यापार की बात आती है, किसानों के हितों की बात आती है, जब हमारी रणनीतिक स्वायत्तता की बात आती है, जब मध्यस्थता के विरोध की बात आती है, तो सरकार बहुत स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि अगर कोई हमसे असहमत है, तो भारत के लोगों को बताए कि क्या वे किसानों के हितों की रक्षा के लिए तैयार नहीं हैं। क्या वे रणनीतिक स्वायत्तता को महत्व नहीं देते हैं। लेकिन हम देते हैं। इसे बनाए रखने के लिए हमें जो कुछ भी करना होगा, हम करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि उस वक्त अमेरिका ने फोन कॉल किए, दूसरे देशों ने भी फोन कॉल किए। यह कोई राज नहीं है। कम से कम मेरे मामले में मेरे पास आए हर अमेरिकी फोन कॉल मेरे एक्स अकाउंट में मौजूद है। ऐसा होता ही है कि जब किसी देश में कुछ होता है तो हर देश दूसरे को कॉल करता ही है।

अर्धसैनिक बलों में साइबर अपराधियों की घुसपैठ

नई दिल्ली
देश में साइबर अपराध के जरिए ठगी होने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सरकारी एवं निजी संस्थानों को टारगेट करने के अलावा आम व खास लोगों को भी साइबर अपराधी निशाना बना रहे हैं। बिना मांगे लोन देना व उसके बाद खाता खाली कर देना, आईटीआर भरने के नाम पर रिफंड उड़ा लेना और लोन देने की बात कह कर खाता खाली कर देना, ऐसे नए नए मामले सामने आ रहे हैं। ऑनलाइन ठगी की वारदात भी हो रही हैं। परिचित के नाम पर जानकारी लेकर आर्थिक नुकसान पहुँचाने की वारदात भी देखने को मिल रही हैं। ताजा मामला सीआरपीएफ के सिपाही/जीडी अनिल सोरेन, जो वर्तमान में जी/95 बटालियन मच्छोदरी पार्क वाराणसी कैंप में तैनात है, के साथ हुआ है। एसबीआई योनो एप के नाम पर सिपाही के साथ ठगी हुई है। उसके खाते से 5,72,500 रुपये निकल गए। जानकारी के मुताबिक, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात सिपाही अनिल सोरेन के मोबाइल नंबर पर 16 अगस्त को एक कॉल आई थी। फोन करने वाले पूछा कि आपका एसबीआई योनो एप में कोई समस्या तो नहीं है।

सिपाही ने बताया कि यूजर नेम तथा पासवर्ड लॉग इन नही हो रहा है। फोन करने वाले ने कहा कि आपका योनो एप काफी पुराने वर्जन का है। हम आपके व्हाट्सप्प पर नया वर्जन वाला एप्लीकेशन भेज रहे हैं। इसमें आप यूजरनेम या पासवर्ड डालिए। इसके बाद आपका एप खुल जाएगा। सिपाही ने एप पर यूजर नेम पासवर्ड लॉग इन कर दिया। इसके बाद योनो एप पर 4 घंटे का समय शुरू हो गया। यह टाइम खत्म होने के बाद आपका एप चालू हो जाएगा।

अनिल अंबानी पर 2000 करोड़ की धोखाधड़ी का केस दर्ज

नई दिल्ली
बैंक धोखाधड़ी मामले में आरकॉम और अनिल अंबानी से जुड़े परिसरों की सीबीआई तलाशी ले रही है। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने कथित बैंक धोखाधड़ी के सिलसिले में शनिवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसके परिसरों की तलाशी ली। इस धोखाधड़ी से भारतीय स्टेट बैंक को 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि एजेंसी आरकॉम और उसके प्रमोटर

निदेशक अनिल अंबानी से जुड़े परिसरों की तलाशी ले रही है। सीबीआई ने यह कार्रवाई भारतीय स्टेट बैंक की शिकायत के आधार पर की है, जिसने 13 जून को इन संस्थाओं को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बाद एजेंसी से संपर्क किया था। रिपोर्टिंग और प्रबंधन नीति के अनुसार की गई थी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले महीने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा था, '24 जून, 2025 को बैंक ने आरबीआई को धोखाधड़ी के वर्गीकरण की सूचना दी थी और अब वह सीबीआई में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही है।' उन्होंने बताया था कि आरकॉम में एसबीआई के ऋण जोखिम में 26 अगस्त, 2016 से प्रभावी 2,227.64 करोड़ रुपये की निधि-आधारित मूल बकाया राशि और 786.52 करोड़ रुपये की गैर-निधि-आधारित बैंक गारंटी शामिल है।

सट्टेबाजी: कर्नाटक के कांग्रेस एमएलए केसी वीरेंद्र गिरफ्तार

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बताया कि कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र कुमार उर्फ 'पप्पी' को कथित अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी मामले में शनिवार को सिक्किम से धन शोधन निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। संघीय जांच एजेंसी ने यह भी बताया कि उसने शुक्रवार को कई राज्यों में की गई छापेमारी के बाद 12 करोड़ रुपये नकद (लगभग एक करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा सहित), 6 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण, लगभग 10 किलोग्राम चांदी और चार वाहन जब्त किए।

ईडी ने बताया कि चित्रदुर्ग के 50 साल के विधायक को शुक्रवार को सिक्किम की राजधानी गंगटोक में एक नामित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया और बंगलूरू की न्यायिक अदालत में पेश करने के लिए ट्रांजिट रिमांड हासिल की गई। ईडी का बंगलूरू जोन मामले की जांच कर रहा है।

कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है भारत: मोहन भागवत

छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र)
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि अगर पारंपरिक खेती और देशी गायों के पालन को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ा जाए, तो भारत कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है। भागवत 28वें ज्येष्ठ पशुवैद्य प्रतिष्ठान के स्थापना दिवस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान किसानों, पशु चिकित्सा से जुड़े स्नातकों और विशेषज्ञों को सम्मानित किया गया। भागवत ने कहा कि आज दुनिया में जो अस्थिरता है, वह बताती है कि भारत को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर

खेती और पशुपालन को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ा जाए, तो इससे किसानों को लाभ होगा और देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा।

आरएसएस प्रमुख ने यह भी कहा कि पशु चिकित्सक उन जीवों की पीड़ा को समझने की कला जानते हैं, जो बोल नहीं सकते और उपचार के समय विरोध नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि प्राचीन पशु चिकित्सा विशेषज्ञ शालिहोत्र ने घोड़े की उम्र और गुणवत्ता जानने का विज्ञान बताया था। यह परंपरा हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने आगे कहा कि अगर पश्चिमी तकनीक को जरूरत के अनुसार अपनाया जाए और उसे भारतीय खेती और पशुपालन के तरीकों के साथ जोड़ा जाए, तो इससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा। लोगों का भरोसा देशी गायों और पारंपरिक खेती के तरीकों पर फिर से बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय कृषि को आधुनिक तरीके से विकसित करके हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ सकते हैं। इस मौके पर पशुपाल के क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले किसानों और पशु चिकित्सकों को आदर्श किसान, आदर्श पशु चिकित्सक, उत्कृष्ट पशु चिकित्सक और आदर्श प्रोफेसर जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पशु चिकित्सा विज्ञान में सबसे ज्यादा अंक लाने वाले और अलग-अलग क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया और एक स्मारिका भी जारी की गई।

कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद वापस छोड़ा जाए', सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

एजेंसी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर अपने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए एक नया अंतरिम फैसला सुनाया है। इस फैसले को अब पूरे देश में लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में बदलाव करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उनके मूल इलाकों में ही छोड़ा जाएगा, लेकिन रेबीज (रेबीज) पीड़ित या आक्रामक कुत्तों को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने (फीडिंग) पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इसके बजाय, नगर निगम (एमसीडी) को कुत्तों के लिए विशेष फीडिंग स्थल बनाने का निर्देश दिया गया है, ताकि व्यवस्थित तरीके से उनकी देखभाल हो सके। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ निर्धारित जगहों पर ही कुत्तों की फीडिंग की जाएगी। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट

किया है कि अगर कोई इन नियमों की अवहेलना करता हुआ पाया गया, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को फीडिंग करने की अनुमति नहीं दी है। तीन जजों की बेंच, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया, ने यह निर्णय लिया है। इसके साथ ही देशभर की सभी अदालतों में लंबित संबंधित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का भी आदेश दिया गया है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट का आदेश केवल दिल्ली-एनसीआर तक सीमित था, लेकिन अब इसे पूरे भारत में लागू करने का निर्णय लिया गया है। अदालत ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण यह समस्या बढ़ी है, इसलिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। देशभर की अदालतों में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने से एकरूपता सुनिश्चित होगी और नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा। बता दें कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को लेकर फिक्र जाहिर करते हुए एमसीडी और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल (एनडीएमसी) को तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने और हटाने का निर्देश दिया था। अपने फैसले में कहा, बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

सिद्धारमैया की जीत के खिलाफ भाजपा ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करायी

एजेंसी
बेंगलुरु। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कर्नाटक इकाई ने 2018 के बादामी विधानसभा चुनावों के दौरान कथित वोट खरीद-फरोख्त और मुख्यमंत्री सिद्दारमैया की इस चुनाव में जीत के खिलाफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज करायी। भाजपा की यह शिकायत पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधान परिषद सदस्य सीएम इब्राहिम के सार्वजनिक बयानों पर केंद्रित है, जो वीडियो और सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हुए हैं। श्री इब्राहीम ने अपने बयानों में दावा किया था कि उन्होंने और उनके एक सहयोगी ने बादामी निर्वाचन क्षेत्र में श्री सिद्दारमैया की जीत

सुनिश्चित करने के लिए एक घर बनाकर तथा पैसे उधार लेकर 3,000 वोट खरीदे और इसके वास्ते लिया गया ऋण चुनाव के छह महीने बाद चुकाया गया था। भाजपा ने तर्क दिया कि यदि ये दावे सही हैं, तो ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(1)(बी) का उल्लंघन हैं, जो रिश्वतखोरी और वोटों में हेराफेरी से संबंधित है, और मतदाता धोखाधड़ी के समान है। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान एक और कथित उल्लंघन की ओर भी इशारा किया, जिसमें अरासीकेरे विधायक शिवलिंगगौड़ा का एक वीडियो दिखाया गया था जिसमें कहा गया था कि हासन लोकसभा क्षेत्र में सात करोड़ रुपये वितरित किए जाने चाहिए। पार्टी ने इसे संभावित वोट-खरीद का एक और उदाहरण बताया और विधायक के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग की। शिकायत में पूर्व मंत्री डॉ. सीएन अश्वथनारायण और राज्य कानूनी प्रकोष्ठ के समन्वयक वसंत कुमार सहित भाजपा नेताओं ने कहा है कि अगर इस तरह के बयानों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो चुनावी व्यवस्था में जनता का विश्वास कम होगा और चुनाव आयोग की निष्पक्षता से समझौता होगा। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री और श्री इब्राहिम आयोग को सभी प्रासंगिक दस्तावेज़ और सबूत उपलब्ध कराएं । भाजपा ने कर्नाटक की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए चुनावी कानूनों की जवाबदेही और सख्त प्रवर्तन की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है।

पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद नागपुर में संघ के विजयादशमी उत्सव के होंगे मुख्य अतिथि

नागपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (रा.स्व.संघ) के वार्षिक विजयादशमी उत्सव के लिए इस वर्ष भी एक विशेष आमंत्रित अतिथि की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र के नागपुर के रेशीमबाग मैदान पर आगामी 12 अक्टूबर को आयोजित होने वाले संघ के विजयादशमी उत्सव में इस बार पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद मुख्य अतिथि होंगे। यह जानकारी शुक्रवार को संघ के प्रचार विभाग ने दी। संघ के प्रचार विभाग ने बताया कि विजयादशमी (दशहरा) का उत्सव रा. स्व. संघ के लिए सत्य पर असत्य की विजय और शक्ति की उपासना के प्रतीक के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यही नहीं इसी पावन अवसर पर वर्ष 1925 में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। इसलिए यह दिवस संघ के लिए केवल धार्मिक पर्व ही नहीं बल्कि उसका स्थापना दिवस भी है, जिसे संघ हर वर्ष बड़े उत्साह के साथ मनाता है। प्रचार विभाग ने बताया कि इस अवसर पर संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत देश और समाज से जुड़े समसामयिक मुद्दों पर अपना संबोधन देंगे। पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की संघ के इस उत्सव कार्यक्रम में उपस्थिति को विशेष महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि वे देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर कार्य कर चुके हैं। उनका संघ के मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित होना एक गौरवपूर्ण बात है। इस कार्यक्रम में हजारों स्वयंसेवक पारंपरिक गणवेश में संघ की शाखा पद्धति का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही संघ के विचारों को दर्शाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे।इस संदर्भ में संघ के प्रचार विभाग ने कहा, देश के पूर्व राष्ट्रपति जैसे गरिमामय व्यक्तित्व का इस कार्यक्रम में सहभागी होना हमारे लिए गौरव की बात है। हमें विश्वास है कि यह आयोजन राष्ट्रीय चेतना को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। पिछले कुछ वर्षों में संघ के मंच पर उपस्थित होने वाले राम नाथ कोविंद दूसरे पूर्व राष्ट्रपति होंगे।

भारत में आतंकी हमले कराकर कोई बच नहीं सकता: पीएम मोदी

एजेंसी
गयाजी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से एक बार फिर देश के दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया है। गयाजी में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में आतंकवादी भेजकर या हमले कराकर कोई बच नहीं सकता है। इस दौरान, उदाहरण देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के जरिए पहलगाम का बदला लिया, जिसका वादा वह बिहार की धरती से करके गए थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षानीति की नई लकीर खींच दी है। अब भारत में आतंकी भेजकर, हमला करके कोई बच नहीं सकता। आतंकवादी चाहे पाताल में क्यों न छिप जाएं, भारत की मिसाइलें उन्हें दफन करके ही रहेंगी। उन्होंने कहा कि बिहार चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की धरती है। जब किसी

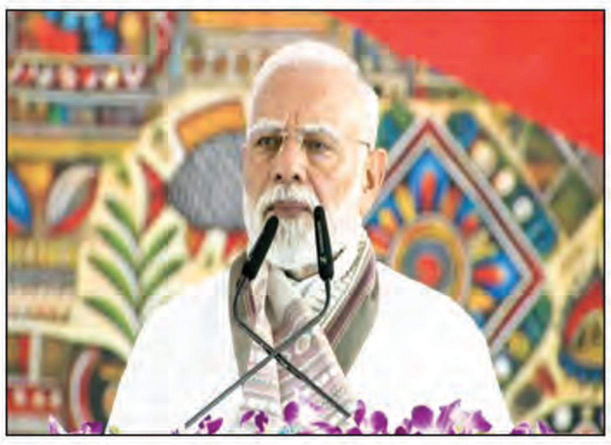

दुश्मन ने भारत को चुनौती दी है, बिहार देश की ढाल बनकर खड़ा हुआ है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, यह बिहार की धरती की ताकत है कि यहां लिया हुआ हर संकल्प कभी खाली नहीं जाता है। इसलिए जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछकर मारा गया, मैंने बिहार की धरती से आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। आज दुनिया देख रही है कि बिहार की धरती से लिया गया वह संकल्प पूरा हो चुका है।

प्रधानमंत्री मोदी ने याद दिलाते हुए कहा कि उधर से पाकिस्तान हमारे ऊपर ड्रोन हमले कर रहा था और मिसाइलें दाग रहा था, इधर भारत पाकिस्तान की मिसाइलों को तिनके की तरह बिखेर रहा था। पाकिस्तान की एक भी मिसाइल हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाई।÷इससे पहले, पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के गयाजी में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। ये परियोजनाएं बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शहरी विकास और जल आपूर्ति जैसे क्षेत्रों से संबंधित हैं।

झील में डूबा यमुनोत्री का पड़ाव स्यानाचट्टी, निचले इलाकों को खतरा

उत्तरकाशी। विश्व प्रसिद्ध धाम यमुनोत्री के पड़ाव स्यनाचट्टी में यमुना नदी पर झील बनने से स्यानाचट्टी जलमग्न हो गया है। यदि अचानक झील फूटती है तो निचले इलाकों में भारी तबाही हो सकती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के अन्तर्गत स्यानाचट्टी में यमुना नदी पर झील बनने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। खासकर खरादी कस्बे और जल विद्युत परियोजना को झील के अचानक टूटने से भारी नुकसान की आशंका है। इससे स्थानीय लोगों में दहशत है। बाद कुपडा गदेरे में भारी मलबा आने से स्यानाचट्टी कस्बे में यमुना नदी पर बड़ी अस्थाई झील बन गई है। इसमें स्यानाचट्टी कस्बे के एक बड़े भाग में बने घर, होटल, गढ़वाल मंडल विकास निगम और बेसिक व माध्यमिक स्कूल डूब गए हैं।पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते स्यानाचट्टी के पास के गाड़-गदेरों में मलबा-बोल्डर जमा हो गए हैं। इससे यमुना नदी का प्रवाह बाधित हुआ और पानी रुकने से करीब आधा किलोमीटर लंबी और लगभग ढाई से तीन सौ मीटर चौड़ी झील बन गई। इस झील के बढ़ते जलस्तर में यमुनोत्री हाईवे पर बना मोटर पुल और स्यानाचट्टी कस्बा जलमग्न हो गया है। कस्बे में लगभग

30 घर और होटल हैं। हर तरफ पानी-पानी होने से स्थानीय लोगों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। क्षेत्र के गांवों-कुपड़ा, कुनसाला, त्रिखली व ओजरी में दहशत का माहौल है। होटल-मकान सब झील में डूबने से लोगों को भारी नुकसान की चिंता सताने लगी है। साथ ही पुजार, कुथनोंर, उपली खरादी, निचली खरादी समेत निचले क्षेत्रों में यमुना किनारे बसे लोग दहशत में आ गए हैं। प्रशासन ने बड़कोट तक अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्क व सावधान रहने के लिए कहा गया है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी शांत आर्य ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से तमाम घर और होटल खाली करा दिए हैं। साथ ही लोगों के लिए क्षेत्र से दूर रहने की सलाह जारी की गई है। एसडीआरएफ, पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर रहकर स्थिति पर पूरी रात भर नजर बनाए रखी। झील से पानी की निकासी को एनडीआरएफ की टीम भी उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची रही है।

संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक, पेड़ के सहारे दीवार फांदकर अंदर घुसा युवक

एजेंसी
नई दिल्ली । संसद भवन की सुरक्षा में एक बार फिर सेंध लगी है। शुक्रवार को एक शख्स पेड़ पर चढ़ते हुए दीवार फांदकर अंदर घुस गया। हालांकि, सुरक्षाकर्मियों ने घुसपैठिए को पकड़ लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है।

यह घटना संसद के मानसून सत्र के समाप्त होने के एक दिन बाद हुई है। बताया जा रहा है कि एक शख्स पेड़ के सहारे दीवार पर चढ़ा और फिर संसद भवन परिसर के अंदर कूद गया। रेल भवन की तरफ से इस व्यक्ति ने दीवार फांदी। इसके बाद वह नई संसद भवन के गरुड़ द्वार तक पहुंच गया। वह सुबह करीब 6.30 बजे संसद भवन में घुसा। उस शख्स को वहां घुमते हुए देखकर संसद भवन में मौजूद सिक्योरिटी ने उसे पकड़ लिया।

सुरक्षा में सेंध की एक ऐसी ही घटना पिछले साल भी हुई थी, जब 20 साल की उम्र का एक व्यक्ति संसद भवन एनेक्सी में घुस गया था। इस घटना का एक कथित वीडियो भी सामने आया था, जिसमें संदिग्ध व्यक्ति, जो शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहने हुए था, सशस्त्र सीआईएसएफ कर्मियों द्वारा पकड़े हुए दिखाई दे रहा था। तलाशी के दौरान उस व्यक्ति के पास से कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं

मिली। 2023 में भी संसद हमले के बरसी के दिन भारी सुरक्षा चूक की घटना हुई। सागर शर्मा और मनोरंजन डी, दो युवक संसद में जारी कार्यवाही के बीच लोकसभा कक्ष में घुस गए थे। इन लोगों ने संसद में दर्शक दीर्घा से कूदने के बाद लोकसभा कक्ष के अंदर पीले रंग का धुआं छोड़ा था। हालांकि, सदन में मौजूद सांसदों ने दोनों को दबोच लिया। उसी समय, संसद के बाहर नीलम आजाद और अमोल शिंदे ने भी पीले रंग का धुआं छोड़ा था। इस मामले में कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अन्य दो आरोपियों में महेश कुमावत और ललित झा शामिल थे। ललित झा को पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड माना जाता है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा चूक मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में 900 पन्नों से अधिक की चार्जशीट दायर की थी।

कांग्रेस नीत यूडीएफ का पत्रकारों के लिए पेंशन वृद्धि और बीमा का वादा

तिरुवनंतपुरम। केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वी.डी. सतीशन ने कहा कि कांग्रेस नीत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) राज्य में अगले विधानसभा चुनावों में सत्ता में आने पर पत्रकारों की पेंशन में इजाफा करेगा और एक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करेगा। श्री सतीशन ने यह आश्वासन वरिष्ठ पत्रकार मंच केरल के यहां आयोजित अखिल भारतीय वरिष्ठ पत्रकार सम्मेलन के प्रतिनिधि सत्र का उद्घाटन करते हुए दिया। उन्होंने कहा कि पेंशन में 'उचित वृद्धि और समय पर वितरण' किया जाएगा। उन्होंने पत्रकारों से आग्रह किया, 'वे इस आश्वासन को रिकॉर्ड कर लें और यूडीएफ के सत्ता में आने पर मुझे जवाबदेह ठहराएँ।' विपक्षी नेता ने मीडियाकर्मियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक मीडिया आयोग के गठन का भी आह्वान किया। उन्होंने आरोप लगाया, 'भारत में, मनगढ़ंत आरोपों में दो पत्रकारों की गिरफ़्तारी मीडिया-विरोधी अभियान का हिस्सा है। केंद्र सरकार मीडिया को एक और सरकारी विभाग बना देना चाहती है। प्रवर्तन निदेशालय की धमकी के डर से बड़े मीडिया घराने भी चुप हैं।÷ श्री सतीशन ने सचिवालय में पत्रकारों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने और सरकार विरोधी रिपोर्टों के स्रोतों की पहचान के लिए जाँच शुरू करने के लिए केरल सरकार की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये कदम प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के समान हैं। एक महीने की जेल के बाद विधायकों और मंत्रियों को अयोग्य ठहराने के केंद्र के प्रस्तावित कानून पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि यह कदम 'स्पष्ट रूप से अलोकतांत्रिक' है। वैश्विक रुझानों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया भर के सत्तावादी शासक असहमति जताने वाले पत्रकारों को निशाना बना रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार टी. शशि मोहन (उपाध्यक्ष, एसजेएफ केरल), सुरेश एडप्पल (महासचिव, केयूडब्ल्यूजे) और जे. अजित कुमार ने भी सभा को संबोधित किया।

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश का राहुल गांधी ने किया स्वागत

एजेंसी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर अपने पुराने आदेश में संशोधन करते हुए शुक्रवार को एक नया अंतरिम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा है कि अब वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उनके मूल इलाकों में ही छोड़ा जाएगा, लेकिन रेबीज से पीड़ित या आक्रामक कुत्तों को छोड़े जाने की अनुमति नहीं होगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'मैं आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के संशोधित निर्देशों का स्वागत करता हूं, क्योंकि यह पशु कल्याण और जन सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। यह

दृष्टिकोण न केवल करुणामय है, बल्कि वैज्ञानिक तर्क पर आधारित भी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उनके मूल इलाकों में ही छोड़ा जाएगा, लेकिन रेबीज (रेबीज) पीड़ित या आक्रामक कुत्तों को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही, सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने (फीडिंग) पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इसके बजाय, नगर निगम (एमसीडी) को कुत्तों के लिए विशेष फीडिंग स्थल बनाने का निर्देश दिया गया है ताकि व्यवस्थित तरीके से उनकी देखभाल हो सके। कोर्ट ने आगे कहा है कि सिर्फ निर्धारित जगहों पर ही कुत्तों की फीडिंग की जाएगी। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई इन नियमों की अवहेलना करता हुआ पाया गया, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को फीडिंग करने की अनुमति नहीं दी है। तीन जजों की बेंच, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया, ने यह निर्णय लिया है। इसके साथ ही देशभर की सभी अदालतों में लंबित संबंधित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का भी आदेश दिया गया है इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट का आदेश केवल दिल्ली-एनसीआर तक सीमित था, लेकिन अब इसे पूरे भारत में लागू करने का निर्णय लिया गया है। अदालत ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण यह समस्या बढ़ी है।

आयोग का ध्यान नाम हटाने पर नहीं जोड़ने पर हो : कांग्रेस

एजेंसी
नई दिल्ली। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर फिर हमला करते हुए कहा कि उसका ध्यान मतदाता सूची से नाम हटाने पर नहीं बल्कि तथ्यों की जांच परख कर नाम जोड़ने पर होना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए आयोग जो काम कर रहा है उसका मकसद मतदाता सूचियों को स्पष्ट और पारदर्शी बनाना नहीं बल्कि लोकतंत्र को नष्ट करना ज्यादा है। पार्टी के संचार विभाग के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों के ठीक बाद बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव आयोग ने सर्वेक्षण कराया और कहा कि मतदाता सूचियां पहले से ही लगभग

पूर्ण सटीक पर हैं लेकिन कागजी कार्यवाही और जागरूकता की कमी के कारण कई पात्र मतदाताओं का नामांकन नहीं हो पाया है।उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से, चुनाव आयोग ने जनवरी 2025 तक बिहार की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं समझी थी। तब से कुछ बदला भी नहीं है तो फिर मतदाता सूची पुनरीक्षण की जरूरत नहीं थी और ऐसा लगता है कि यह चुनाव आयोग के जरिए महज सत्ता पक्ष के गठबंधन को बचाने की कोशिश मात्र है। श्री रमेश ने कहा कि बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य मतदाता सूचियों को व्यवस्थित बनाना और उसकी शुद्धता और सफाई कम तथा लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश ज़्यादा है।

राहुल गांधी कर रहे संवैधानिक संस्थाओं को शक के दायरे में लाने का प्रयास : शाह

एजेंसी
कोच्चि । केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कोच्चि में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को मान न दिए जाने का आरोप लगाया। शाह आगामी महत्वपूर्ण स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर भाजपा के राज्य नेतृत्व को तैयार करने हेतु शुक्रवार को केरल की वाणिज्यिक राजधानी कोच्चि के एक दिवसीय दौरे पर हैं।

एक कार्यक्रम में शाह ने बताया कि देश को नुकसान पहुंचाने वाली स्थितियां पिछली सत्ता की देन है। उन्होंने कहा, 'जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण देश के लिए नासूर जैसा है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इन तीनों की जगह 'पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस' की शुरुआत हुई है और जिसे पूरा देश

अनुभव कर रहा है। करप्शन को दूर करने का प्रयास देश के पीएम ने किया है। चूंकि स्थिरता है, इसलिए लंबे समय तक नीतियां चल रही हैं। इस 11 साल के कालखंड को जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि जनता के देश में पहले जो सवाल था कि भविष्य कैसा होगा, वो अब नहीं है। आज 140 करोड़ लोग मानते हैं कि 2047 में भारत टॉप पर होगा और इसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। वहीं, राहुल गांधी को लेकर पूछे गए सवाल पर बोले, जब से वो मुखिया बने हैं तब से संवैधानिक संस्थाओं को शक की नजर से देख रहे हैं। अभी जो एसआईआर हो रहा है, वो 2003 में भी हुआ था, 1961 में भी हुआ था और 1970 में भी हुआ था। तो अब समस्या क्या है? अगर एसआईआर से कोई भी नागरिक या राजनीतिक पार्टी संतुष्ट नहीं है, तो वह असेंबली के रिटर्निंग ऑफिसर, जिला कलेक्टर और राज्य के चीफ इलेक्शन ऑफिसर के सामने अपील कर सकता है। शाह ने सदन में पेश तीन विधेयकों को लेकर कहा कि लोकतंत्र में नैतिकता का स्तर बनाए रखने की जिम्मेदारी सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों की है। ये बिल किसी पार्टी के लिए नहीं है। ये बिल भाजपा के मुख्यमंत्रियों पर भी लागू होगा और प्रधानमंत्री पर भी लागू होगा। बता दें कि मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) बिल 2025, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल 2025 और संविधान (130वां संशोधन) बिल 2025 पेश किए थे। जिसमें प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केन्द्र या राज्य सरकार के मंत्री के रूप में शासन नहीं चला सकता है। विपक्ष ने इन बिलों का विरोध किया।

स्थायी समिति की बैठक में नागरिकों के हित में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास

एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नागरिक सुविधाओं, स्वच्छता, शिक्षा एवं जन-सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और नागरिक हित से जुड़े कई प्रस्ताव पारित करते हुए अधिकारियों को ठोस निर्देश दिए गए। अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि दिल्ली नगर निगम का दायित्व केवल कूड़ा प्रबंधन तक सीमित नहीं है बल्कि नागरिकों की बुनियादी सुविधाओं, सुरक्षित वातावरण और शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देना है। बैठक में पार्षदों को कार्य करने के निर्देश दिए। सभी सार्वजनिक शौचालयों की साफ-सफाई और मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया जाए, भवन निर्माण के नक्शे पास करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाए, जिन नागरिकों के पास अनुमोदित नक्शा हो, उन्हें बेवजह तंग न किया जाए, निगम के अधीन आने वाले सभी स्विमिंग पूलों की नियमित जाँच की जाए ताकि डूबने जैसी कोई दुर्घटना न हो सके, दिल्ली में चल रहे अवैध स्पा सेंटरों पर सख्त कार्रवाई की जाए। जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उनके खिलाफ तुरंत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, निगम स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने पर ध्यान दिया जाए। साथ ही जर्जर स्कूल भवनों की जाँच कर उनकी मरम्मत हेतु शीघ्र कदम उठाए जाएं, सफाई कार्य में लापरवाही बरतने वाली कूड़ा उठाने वाली कंपनियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए और अनुबंधीय प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाया जाए।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की निंदा की

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बुधवार सुबह अपने निवास कार्यालय में जन सुनवाई कर रहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि जिस तरह हमलावर की एक दो दिन पहले से मुख्यमंत्री के सरकारी एवं निजी आवास की रेकी करने की सी.सी.टी.वी. फुटेज सामने आई है उससे यह सम्भावना लगती है की यह एक सोची समझी साजिश हो सकती है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नही है और मुख्यमंत्री या भाजपा ऐसे हमले से भयभीत नही होने वाले। भाजपा के नेता अपना सार्वजनिक जनसंवाद पहले से अधिक सघनता से जारी रखेंगे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हमले का सही कारण तो पुलिस जांच पूर्ण होने पर ही सामने आयेगा पर प्रारम्भिक जानकारी अनुसार यह हमलावर पूर्व में भी दो बार अपराधिक घटनाओं में संलिप्त रह चुका है। इसे यह लगता हैं कि यह कोई सुनियोजित साजिश है। सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री पर हमले के बाद दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने जिस तरह की वीडियो पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली वह निंदनीय है और कहीं ना कहीं हमलावर को नैतिक समर्थन देने के समान है। उन्होंने कहा कि सौरभ भारद्वाज इस तरह का ट्वीट कर हमलावर अपरोक्ष प्रोत्साहन समझ से परे है।

मनुष्य बने रहने की कोशिश ही समकालीनता है - प्रो. नंदकिशोर आचार्य

नई दिल्ली। हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय डॉ. नगेंद्र स्मृति व्याख्यानमाला के दूसरे दिन साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नंद किशोर आचार्य ने रस की समकालीनता विषय पर अपना विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि अपने समय में मनुष्य बने रहने की कोशिश ही समकालीनता है। कला व ध्यान ही मनुष्य के विकास की प्रक्रिया है। नंद किशोर आचार्य ने बताया कि रस को समझने के लिए रस सूत्र की जगह सहृदयता व रसानुभूति की अधिक आवश्यकता है। रस सम्पूर्ण कला शास्त्र का सिद्धांत है। कला व ध्यान मनुष्य के विकास की प्रक्रिया का एक रूप है। उन्होंने कहा कि मनुष्य का जन्म सृजनात्मकता का ही एक रूप है जो कि उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। जिसमें मनुष्य के आत्म की सृजनात्मकता भी शामिल है जो कि नए आयामों को उद्घाटित करती है। उन्होंने कहा कि आत्मसृजन का आनंद ही रस का केंद्रीय भाव है। अतिथियों का स्वागत व विषय की स्थापना करते हुए प्रो. आशुतोष कुमार ने रस को सृजनात्मकता के आनंद में उपस्थित माना। समकालीन समय में रस को समझने की प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने का प्रश्न वक्ताओं के समक्ष रखा।

दिल्ली विधानसभा में ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को लेकर उच्चस्तरीय बैठक

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा भवन में 24-25 अगस्त को होने वाली 'ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस' की तैयारियों की समीक्षा को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक हुई। बैठक में दिल्ली पुलिस आयुक्त एसबीके सिंह, स्पेशल सीपी ट्रैफिक के जगदीशन, स्पेशल सीपी सुरक्षा जसपाल सिंह, डीसीपी सुरक्षा मनस्वी जैन, जॉइंट सीपी (नॉर्थ एवं सेंट्रल) मधु वर्मा और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में दिल्ली पुलिस आयुक्त एसबीके सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष गुप्ता को आश्वस्त किया कि कार्यक्रम के लिए चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी और किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं होगी। सभी अतिथियों को 'राज्य अतिथि' का दर्जा दिया जाएगा और उनके साथ दिल्ली पुलिस के विशेष प्रोटोकॉल एवं सुरक्षा अधिकारी तैनात रहेंगे। हवाई अड्डे से लेकर ताज होटल में ठहरने और विधानसभा तक आने-जाने के लिए विशेष यातायात व्यवस्था की जाएगी ताकि सभी गणमान्य अतिथियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

उप राष्ट्रपति चुनाव में राजग का पलड़ा भारी

एजेंसी
नई दिल्ली। उप राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा में संख्या बल के आधार पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को स्पष्ट बहुमत हासिल होने के कारण उसके उम्मीदवार का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। उप राष्ट्रपति चुनाव के लिए राजग ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन को जबकि इंडिया गठबंधन ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। श्री राधाकृष्णन ने अपना नामांकन पत्र दायर कर दिया है जबकि श्री रेड्डी नामांकन दायर करने के अंतिम दिन गुरुवार को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उप राष्ट्रपति चुनाव आगामी नौ सितम्बर को निर्धारित है। उप राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सांसद मतदान करते हैं। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 हैं लेकिन एक सीट खाली होने की वजह से मतदान में 542 सदस्य हिस्सा ले सकेंगे। राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या 245 हैं जबकि छह सीटें खाली हैं जिसकी वजह से

239 सदस्य ही वोट कर सकते हैं। इस तरह मतदान के पात्र सदस्यों की कुल मौजूदा संख्या 781 है। चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 391 वोटों की आवश्यकता होगी।

दोनों सदनों में संख्याबल और राजनीतिक समीकरण को देखते हुए राजग के लोकसभा में 293 और राज्यसभा में कम से कम 134 सांसद हैं। इससे राजग के पास कम से कम 427 वोटों का ठोस आंकड़ा है, जो बहुमत के लिए जरूरी 391 वोटों के आंकड़े से बहुत अधिक है। इस तरह राजग उम्मीदवार सी. पी. राधाकृष्णन के जीतने की प्रबल संभावना है। इंडिया गठबंधन के लोकसभा में 249 और राज्यसभा में 105 सांसद हैं। इस तरह गठबंधन के कुल 354 वोट होते हैं जो बहुमत के लिए आवश्यक आंकड़े 392 से कम है।

अगर इंडिया गठबंधन आम तौर पर सरकार के पक्ष में वोट करने वाली वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल जैसी छोटी पार्टियों को भी अपने पक्ष में कर लेती है तो भी वह जीत के जादुई आंकड़े से दूर ही रहेगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के 60 दिनों के भीतर और 19 सितंबर से पहले होना चाहिए। उप राष्ट्रपति चुनाव में मतदान गुप्त मतदान प्रक्रिया से होता है।

राजग उम्मीदवार के नामांकन के समय उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री तथा भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी थे। नामांकन प्रक्रिया के तहत नामांकन पत्रों के चार सेट दाखिल किए गए।

दिल्ली के दरियागंज इलाके में दो मंजिला इमारत गिरी, तीन की मौत

एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली के दरियागंज थाना क्षेत्र में साद्भावना पार्क से सटी सिटी वॉल के किनारे बनी एक इमारत अचानक ढह गई। हादसे में काम कर रहे तीन मजदूरों की मौके पर मौत हो गई। मृतकों की पहचान जुबैर, गुलसागर और तौफीक के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस व राहत दल मौके पर पहुंचे और शवों को लोकनायक जय प्रकाश अस्पताल भेज दिया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही डीडीएमए सहित संबंधित नागरिक एजेंसियों को सूचित किया गया है। फिलहाल राहत व बचाव कार्य जारी है और मलबे में किसी और के दबे होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। पुलिस ने बताया कि तथ्यात्मक जांच के बाद इस संबंध में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दमकल व पुलिस के अनुसार बुधवार दोपहर 12.14 बजे सूचना मिली कि साद्भावना पार्क से सटी सिटी वॉल के पास दो मंजिला मकान गिर गया है। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस व दमकल की तीन गाड़ी पहुंची। पुलिस ने आसपास लोगों की मदद से मलबे से तीन लोगों को बाहर निकाल कर नजदीकी अस्पताल में दाखिल करवाया। जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।

कांग्रेस ने की निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू करने की मांग, संसदीय समिति की रिपोर्ट का दिया हवाला

एजेंसी
नई दिल्ली। राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों का हवाला देते हुए कांग्रेस ने केंद्र सरकार से निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण लागू करने की अपील की है। दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली शिक्षा संबंधी संसदीय समिति की रिपोर्ट को आज ही संसद में पेश किया गया। समिति ने सिफारिश की है कि संसद को ऐसा कानून पारित करना चाहिए, जिसके तहत निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी समुदायों के लिए 15 प्रतिशत, एसटी के लिए 7.5 और ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य किया जाए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी समुदाय के लिए 15 फीसदी, एसटी के लिए 7.5 और ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण लागू करने की मांग की है। रमेश ने कहा कि कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने न्याय पत्र के माध्यम से वादा किया

था कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो संविधान के अनुच्छेद 15(5) को लागू करने के लिए कानून लाया जाएगा, जिससे निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण अनिवार्य हो सके। उन्होंने बताया कि समिति ने अपने अध्ययन में यह बताया कि वर्तमान में निजी संस्थानों में इन वर्गों का प्रतिनिधित्व बेहद कम है। केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तीन प्रमुख निजी उत्कृष्ट संस्थानों के आंकड़ों के अनुसार, केवल 0.89 प्रतिशत छात्र एससी वर्ग से हैं, 0.53 प्रतिशत एसटी वर्ग से और 11.16 प्रतिशत छात्र ओबीसी वर्ग से हैं। समिति ने कहा कि यह आंकड़े चिंताजनक हैं और इससे स्पष्ट होता है कि बिना कानूनी प्रावधान के सामाजिक न्याय की दिशा में प्रगति संभव नहीं है।

समिति की सिफारिश में यह भी कहा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(5), जिसे 2006 में 93वें संविधान संशोधन के ज़रिए जोड़ा गया था, सरकार को निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू करने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2014 के प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ मामले में अनुच्छेद 15(5) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। इसके बावजूद अब तक संसद ने कोई ऐसा कानून पारित नहीं किया है जो इस अधिकार को लागू कर सके।

बस्तर सांसद ने प्रधानमंत्री को बस्तर दशहरा में शामिल होने को दिया आमंत्रण

एजेंसी
जगदलपुर। बस्तर सांसद महेश कश्यप ने बुधवार को अपनी पत्नी चंपा कश्यप व पुत्री क्षमता कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष एवं बस्तर सांसद महेश कश्यप ने बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर और विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रण दिया। सांसद महेश कश्यप ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए बस्तर दशहरे में समय निकालकर शामिल होने का आश्वासन दिया है।

मुलाकात के दौरान सांसद ने प्रधानमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया और बस्तर में केंद्र सरकार द्वारा संचालित विकास कार्यों के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्र ने विगत 11 वर्षों में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 और 35ए को हटाकर भारत माता के माथे से कलंक मिटाने का साहसिक निर्णय हो या फिर अयोध्या में भगवान श्रीराम मंदिर का निर्माण कराकर भारत की आध्यात्मिक आत्मा को पुनर्जागृत करने का कार्य, इन ऐतिहासिक कदमों ने भारत को विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाई है। सांसद ने यह भी उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और नेतृत्व में बस्तर जैसे आदिवासी बहुल, जल-जंगल-जमीन से समृद्ध लेकिन लंबे समय तक नक्सलवाद से पीड़ित क्षेत्र में आज शांति और विकास की नई राह दिखाई दे रही है। माओवादी हिंसा और अशिक्षा जैसी समस्याओं को समाप्त करने की दिशा में निरंतर प्रयास हो रहे हैं और 2026 तक बस्तर को पूर्ण रूप से नक्सलवाद मुक्त बनाने की ठोस कार्य योजना पर

कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र के कार्यक्रम में स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा बस्तर क्षेत्र का बार-बार उल्लेख किया जाना बस्तर के लिए गर्व का विषय है और इससे यह स्पष्ट होता है कि यह क्षेत्र प्रधानमंत्री के हृदय के कितना निकट है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मारने की नीयत से किया गया था हमला : कपिल मिश्रा

एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला बहुत ही गंभीर मामला है। यह कोई राजनीतिक हमला नहीं है, यह मारने की नीयत से किया गया हमला है। मुख्यमंत्री को गिराकर मारने की कोशिश की गई है, यह अपने आप में भयावह है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले लिया है। यह हमला मुख्यमंत्री निवास सिविल लाइंस राज निवास मार्ग स्थित जन सेवा केंद्र में हुआ। आरोपित की पहचान गुजरात के राजकोट निवासी राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया के रूप में हुई है। मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि यह व्यक्ति मारने के इरादे से आया था। इसके

पास न कोई कागज था न कोई मुद्दा। इसके मोबाइल में मुख्यमंत्री के घर की रेकी के वीडियो मिले हैं। यह व्यक्ति सिर्फ हमला करने के उद्देश्य से ही आया था। मुख्यमंत्री का मनोबल इन हमलों से कम नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री जनसुनवाई के लिए पहले से ज्यादा जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री न रुकेंगी, न झुकेंगी और न ही डरने वाली हैं। लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने एक्स पोस्ट में कहा कि मुख्यमंत्री पर हुआ हमला अत्यंत निंदनीय है और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा प्रहार है। जनसुनवाई का कार्यक्रम लोगों से सीधे जुड़ने का माध्यम है, जहां जनता अपने सवाल और संदेह बिना किसी डर या बाधा के मुख्यमंत्री तक पहुंचा पाती है। ऐसी पवित्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश कदापि स्वीकार नहीं की जा सकती। दोषियों पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि मुख्यमंत्री पर हुआ हमला अत्यंत दुखद, निंदनीय और अस्वीकार्य है। उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा कि दिल्ली के हित के लिए निरंतर कार्यरत एक संवेदनशील और दृढ़निश्चयी महिला नेतृत्व पर इस प्रकार का कायरतापूर्ण आक्रमण लोकतांत्रिक आचरण की मूल भावना के विपरीत है। यह अमर्यादित कृत्य न केवल हमारे लोकतंत्र की साख को आहत करता है, बल्कि समाज में अराजकता फैलाने का घृणित प्रयास भी है।

भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष ने की प्रधानमंत्री से मुलाकात

एजेंसी
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष वानथी श्रीनिवासन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर मोर्चा की उपलब्धियों से अवगत कराया। उन्होंने महिला मोर्चा की गतिविधियों की उपलब्धियों की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी और वीरांगना भारत की 75 प्रेरणादायी महिला स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित विशेष कॉफी टेबल बुक भी भेंट की। मुलाकात के बाद वानथी ने मीडियाकर्मियों से कहा कि पिछले तीन वर्षों में किए गए महिला मोर्चा के कार्यों से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। कमल मित्र अभियान जैसी स्वप्रेरित पहलें, प्रभावशाली दो दिवसीय प्रवास कार्यक्रम, व्यापक जनसंपर्क अभियान और अनेक नवाचारी अभियानों के माध्यम से महिला मोर्चा ने लगातार जमीनी स्तर की महिलाओं से जुड़ने और उन्हें पार्टी तथा सरकार की परिवर्तनकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि मुलाकात के दौरान 37 राज्यों में संगठनात्मक दौरों के अनुभव साझा किए।

इसमें न केवल संगठनात्मक कैडर की शक्ति प्रतिबिंबित होती है, बल्कि उन प्रेरक कहानियों का भी उल्लेख है जिनमें महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र की प्रगति की समान भागीदार बन रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अत्यंत रुचि से सब सुना, मोर्चा के प्रयासों की सराहना की और बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया, जो महिला मोर्चा को और व्यापक स्तर पर पहुंचने और प्रभाव बढ़ाने की प्रेरणा देगा।

पिछले 11 वर्षों में सत्ता पक्ष ने विपक्ष के साथ भेदभाव किया: खरगे

एजेंसी
नई दिल्ली। इंडी गठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने आज संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में बैठक कर उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में एकजुटता का प्रदर्शन किया। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एनसीपी (एससीपी) के प्रमुख शरद पवार, डीएमके सांसद त्रिची शिवा, समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव, शिवसेना (यूबीटी) के संजय राउत, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई समेत कई प्रमुख विपक्षी दलों के नेता उपस्थित थे। इस अवसर पर खरगे ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में सत्ता पक्ष ने विपक्ष के साथ भेदभाव किया है। संसद में बहुमत के बल पर सरकार जनविरोधी कानून पारित करती रही है, जबकि यह सरकार अल्पमत में है। संसद के मानसून सत्र में देश ने देखा कि कैसे बिना विपक्ष की भागीदारी के विधेयकों को जल्दबाजी और मनमानी से पारित किया गया। विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं दिया गया और उन्हें मनमाने तरीके से निलंबित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति देश का दूसरा

सर्वोच्च संवैधानिक पद है, जिसकी गरिमा और निष्पक्षता को बनाए रखना अनिवार्य है। डॉ. एस. राधाकृष्णन जैसे महान व्यक्तित्वों ने इस पद की गरिमा को स्थापित किया था और राज्यसभा में एक स्वस्थ परंपरा को जन्म दिया था। आज वही परंपराएं टूटती दिख रही हैं और विपक्ष को उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। ऐसे समय में विपक्षी दलों ने सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया है कि वे एक ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित करेंगे, जिनका पूरा जीवन संविधान, लोकतंत्र और न्यायिक मूल्यों के प्रति समर्पित रहा हो। राहुल गांधी ने भी इस मौके पर रेड्डी के अनुभव और सोच की सराहना करते हुए कहा कि वे एक ऐसे न्यायाधीश हैं, जिनके पास दशकों का कानूनी अनुभव है और वे संविधान के सच्चे उपासक हैं। रेड्डी ने तेलंगाना में सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

पति-पत्नी और बेटे का मिला शव, दूसरा बेटा लापता

नई दिल्ली। दक्षिणी जिले के मैदानगढ़ी थाना क्षेत्र के सतबाड़ी खर्क गांव में एक ही परिवार के तीन लोगों की खून से सनी लाशें मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस को पीसीआर कॉल मिली थी कि घर नंबर 155 पर खून-खराबा हुआ है, एक लड़के ने हाथ काट लिया है और घर में खून फैला हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जो नजारा देखा, उससे सब दंग रह गए।

पुलिस अधिकारी के अनुसार मृतकों की पहचान प्रेम सिंह (50), पत्नी रजनी (45) और बेटा ऋतिक (24) के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक प्रेम सिंह और ऋतिक के शव घर की निचली मंजिल पर खून से लथपथ पड़े थे, जबकि रजनी का शव पहली मंजिल से बरामद हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही एफएसएल टीम और क्राइम टीम मौके पर पहुंची और सबूत जुटाए।

संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक

एजेंसी
नई दिल्ली। राज्यसभा ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025 को ध्वनि मत से पारित कर दिया, जिससे गुवाहाटी में देश का 22वां और असम का पहला भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। केंद्र सरकार इसके लिए 550 करोड़ रुपये की पूंजीगत सहायता प्रदान करेगी। यह विधेयक एक दिन पहले मंगलवार को लोकसभा से पारित हो चुका है। सरकार के मुताबिक, आईआईएम गुवाहाटी, पूर्वोत्तर भारत में शिलॉन्ग के बाद दूसरा आईआईएम होगा। यह विधेयक गुवाहाटी में स्थापित होने वाले आईआईएम को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का दर्जा भी प्रदान करता है। इसके माध्यम से पूर्वोत्तर भारत में उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने, विश्वस्तरीय प्रबंधन शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने तथा आर्थिक विकास और व्यावसायिक नेतृत्व को सशक्त करने का लक्ष्य है। राज्यसभा में भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किए जाने के बाद विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि यह केवल एक

शैक्षणिक संस्थान की स्थापना नहीं है, बल्कि असम और पूर्वोत्तर भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा कि गुवाहाटी में आईआईएम की मांग लंबे समय से की जा रही थी और आज यह सपना साकार हो रहा है। प्रधान ने कहा कि आईआईटी गुवाहाटी, एनआईटी सिलचर और केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के बीच एक आईआईएम की कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी। अब यह कमी पूरी हो रही है। इस संस्थान से असम के युवाओं को प्रबंधन शिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि विधेयक के माध्यम से भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 में संशोधन कर गुवाहाटी स्थित नए संस्थान को अधिनियम की अनुसूची में शामिल किया जाएगा, जिससे इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त होगा। शिक्षा मंत्री ने सदन से आग्रह किया कि इस विधेयक को तत्काल पारित किया जाए ताकि इसी सत्र में गुवाहाटी में आईआईएम का उद्घाटन कर शैक्षणिक सत्र प्रारंभ किया जा सके। राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी भुवनेश्वर कालिता की अनुमति के बाद विधेयक पर व्यापक चर्चा हुई और अंततः इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। चर्चा के दौरान असम से भाजपा सदस्य कणाद पुरकायस्थ, एजीपी के बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य, गुजरात से रामभाई मोकारिया और तमिलनाडु से एआईएडीएमके के डॉ. एम. थंबीदुरई ने विधेयक का समर्थन करते हुए इसमें भाग लिया। चर्चा के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान ने एक दिन पहले लोकसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान बताया था कि इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार 550 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देगी, जबकि असम सरकार भूमि और बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करेगी। असम सरकार और केंद्र सरकार के बीच इस परियोजना को लेकर गहरा सहयोग रहा है।

राष्ट्रपति सैलून का आम जनता के लिए अनावरण

एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित राष्ट्रीय रेल संग्रहालय में आज ऐतिहासिक राष्ट्रपति सैलून का आम जनता के लिए अनावरण किया गया। इस अवसर पर रेलवे बोर्ड की कार्यकारी निदेशक (विरासत) आशिमा मेहरोत्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय के निदेशक दिनेश कुमार गोयल भी शामिल हुए। यह विशेष प्रदर्शनी 24 अगस्त तक आम दर्शकों के लिए खुली रहेगी। राष्ट्रपति सैलून भारतीय रेलवे की उस गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है, जिसका उपयोग देश के राष्ट्रपतियों द्वारा राजकीय यात्राओं के लिए किया जाता रहा है। प्रदर्शनी का उद्देश्य जनता को इस अनूठे सैलून के इतिहास से अवगत कराना है। इसमें उन राजकीय रेल यात्राओं की झलक मिलती है, जो भारतीय लोकतंत्र और परंपराओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण रही हैं। यह आयोजन भारतीय रेलवे की उस विशिष्ट विरासत को सामने लाता है, जो परंपरा और आधुनिकता का अद्वितीय संगम है। प्रदर्शनी के दौरान दर्शक न केवल राष्ट्रपति सैलून की भव्यता और ऐतिहासिक महत्व को देख सकेंगे, बल्कि भारतीय रेलवे के गौरवशाली अध्यायों से भी रूबरू होंगे। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति सैलून दो विशेष डिब्बों में बंटा है। यह कोच संख्या 9000 और 9001 से मिलकर बना है। पहले कोच संख्या 9000 कार 'ए' में राष्ट्रपति का दफ्तर, बैठक कक्ष, विश्राम कक्ष, अतिथि कक्ष, स्नानघर, आलीशान किचन और शौचालय शामिल है। इस हिस्से में राष्ट्रपति अपनी औपचारिक बैठक और राजकीय कार्य करते थे। यहां 14.5 किलोग्राम चांदी के बर्तन थे, जिनमें राष्ट्रपति खाना खाते थे। वहीं, दूसरे कोच संख्या 9001 कार 'बी' में चिकित्सक और सचिव का केबिन, भोजन कक्ष, रसोईघर तथा पेंट्री स्टोर जैसी सुविधाएं मौजूद है। यह कोच राष्ट्रपति के स्टाफ और टीम के लिए तैयार किया गया गया था। इसकी स्पीड 90 किमी प्रति घंटा है। बोगी में पार्किंग ब्रेक के साथ एयर ब्रेक सिस्टम लगा है। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के कार्यकाल के बाद राष्ट्रपति सैलून का संचालन बंद कर दिया गया। नई दिल्ली के रेल म्यूजियम में फिलहाल इसे रखा गया है।

संपादकीय

पूरे देश के आवारा कुत्तों पर कार्रवाई क्यों नही?

दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली/एनसीआर के नागरिक प्रशासन और स्थानीय निकाय को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इनमें आवारा कुत्तों को पकड़ने, उनकी नसबंदी करने और उन्हें आश्रय गृह में रखने के निर्देश दिये गए हैं।सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई में अड़ंगा डालता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि ह्यएनसीटी-दिल्ली, एमसीडी, एनएमडीसी तुरंत आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए अभियान शुरू करें और खासकर उन इलाकों में जहां आवारा कुत्तों का खतरा ज्यादा है।पीठ ने स्थानीय निकायों को निर्देश दिया कि आठ हफ्तों में वे आवारा कुत्तों को रखने के लिए आश्रय स्थल बनाने की जानकारी दें। अदालत ने कहा कि आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति या संगठन इस काम में आड़े आए तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें।पीठ ने ये भी कहा कि ह्यएमसीडी/एनडीएमसी और दिल्ली एनसीआर के संबंधित प्राधिकरण दैनिक आधार पर आवारा कुत्तों को पकड़ने का रिकॉर्ड रखें और पकड़े जाने के बाद एक भी आवारा कुत्ता वापस छोड़ा नहीं जाना चाहिए और सभी को आश्रय स्थल में रखा जाए।ह्न पीठ ने कहा कि अगर इस मामले में लापरवाही की गई तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे।अदालत ने कहा आवारा कुत्तों के बारे में शिकायत मिलने के चार घंटे के भीतर कार्रवाई होनी चाहिए और कुत्तों की नसबंदी के बाद उन्हें वापस पुरानी जगह न छोड़ा जाए। अदालत ने कहा कि रेबीज की वैक्सीन की उपलब्धता भी चिंता का कारण है। अदालत ने वैक्सीन की उपलब्धता की भी पूरी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि नवजात, छोटे बच्चे किसी भी कीमत पर इन आवारा कुत्तों के शिकार नहीं बनने चाहिए।सुप्रीम कोर्ट ने एक हेल्पलाइन स्थापित करने के भी निर्देश दिए। पीठ ने कहा कि एक हफ्ते में हेल्पलाइन स्थापित की जाए, ताकि इस पर लोग कुत्तों के काटने की घटनाओं को रिपोर्ट कर सकें। न्यायालय ने कहाकि ह्यआवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में रखें, अड़ंगा डालने वालों पर कार्रवाई करें।

जस्टिस पारदीवाला ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि नसबंदी हो चुकी है या नहीं, सबसे पहली चीज है कि समाज आवारा कुत्तों से मुक्त होना चाहिए। एक भी आवारा कुत्ता शहर के किसी इलाके या बाहरी इलाकों में घूमते हुए नहीं पाया जाना चाहिए। हमने नोटिस किया है कि अगर कोई आवारा कुत्ता एक जगह से पकड़ा जाता है और उसकी नसबंदी करके उसे उसी जगह छोड़ दिया जाता है, ये बेहद बेतुका है और इसका कोई मतलब नहीं बनता। आवारा कुत्ते क्यों वापस उसी जगह छोड़े जाने चाहिए और किस लिए? पीठ ने कहा कि हालात बेहद खराब हैं और इस मामले में तुरंत दखल दिए जाने की जरूरत है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने भी अदालत से अपील की कि वे इस मामले में सख्ती से दखल दें ताकि आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान हो सके। मेहता ने कहा कि नसबंदी से कुत्तों की सिर्फ संख्या बढ़नी रुकती है, लेकिन रेबीज का संक्रमण फैलाने की उनकी क्षमता कम नहीं होती।

सवाल यह है कि ये आदेश दिल्ली /एनसीआरके लिए ही क्यों हैं।देश में भी तो नागरिक रहते हैं। उनके लिए क्यों नही। आवारा कुत्तों का आंतक तो पूरे देश में है। देश में कुत्तों के काटने से औसतन प्रति वर्ष 29 हजार से ज्यादा व्यक्ति मरते हैं। यह तो संख्या वह है जो रिपोर्ट हो जाती है। गांव देहात के मामले से रिपोर्ट ही नही हो पाते। न वे खबरों की सुर्खियां बनते हैं।

उत्तर प्रदेश का बिजनौर बहुत छोटा जिला है। यहां हाल ही में 24 जुलाई की शाम थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव झाड़पुरा भागीजोत में खेत पर काम कर रहीं 65 वर्षीय वृद्धा को आवारा कुत्तों के झुंड ने नोच कर मार डाला। तीन अगस्त को हीमपुर दीपा के गांव गांगू नंगला में हिंसक कुत्ते ने हमला कर दो बच्चों सहित 10 लोगों को बुरी तरह से घायल कर डाला। छह जून 2025 को अफजलगढ़ में पांच साल की बच्ची यास्मीन को आवारा कुत्तों के झुंड ने नोच-नोचकर मार डाला. दरअसल, बच्ची मां के साथ दूध लेने गई थी और पीछे रह जाने पर बच्ची कुत्तों के हि लग गई।

23 अक्तूबर 2023 को देश की प्रमुख चाय कंपनियों में से एक वाघ बकरी चाय के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पराग देसाई का निधन हो गया है। मीडिया खबरों के मुताबिक 49 साल के पराग पिछले हफ्ते अहमदाबाद में मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इस दौरान आवारा कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया। खुद को बचाने में वह फिसलकर गिर गए और उन्हें ब्रेन हेमरेज होने से निधन हो गया ।

भारत सरकार के स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय ने पिछले साल संसद में हुए एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि 2019 में 72 लाख 77 हजार 523 कुत्तों के हमले रिपोर्ट हुए। वहीं साल 2020 में कुल 46 लाख 33 हजार 493 कुत्तों के हमलों रिपोर्ट हुए, जबकि साल 2021 में कुल 1701133 कुत्तों के काटने के मामले रिपोर्ट हुए।साल 2022, जुलाई तक भारतीय लोगों पर हुए कुत्तों के हमले की कुल संख्या स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, 14 लाख 50 हजार 666 थी। इन हमलों में कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। ये हमले आवारा और पालतू दोनों कुत्तों के हैं। इसके साथ ही इन हमलों के शिकार, बच्चे, बुजुर्ग और जवान तीनों हुए हैं।

शिक्षा-चिकित्सा को मुनाफाखोरी से बचाने का भागवत-आह्वान

ललित गर्ग

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने इंदौर के एक किफायती कैंसर अस्पताल के उद्घाटन अवसर पर जो बात कही, वह आज की सबसे बड़ी सामाजिक-आर्थिक और नैतिक आवश्यकता को उजागर करती है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शिक्षा और चिकित्सा जैसे बुनियादी क्षेत्रों को मुनाफाखोरी से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि ये सेवा के क्षेत्र हैं, व्यापार के नहीं। हाल के वर्षों में शिक्षा और चिकित्सा का जिस तेजी से बाजारीकरण एवं व्यावसायीकरण हुआ है, सरकार के साथ-साथ निजी क्षेत्र ने इसे धन कमाने का जरिया बनाया है, वह न केवल नये समाज निर्माण की चिन्ताओं बल्कि एक दूषित सोच को दशार्ता है। क्योंकि उसने आम आदमी को बदहाली के कगार पर पहुंचाया है। महंगी शिक्षा ने जहां अभिभावकों का बजट हिला दिया है, वहीं चिकित्सा के नाम पर मुनाफाखोरी ने लाखों परिवारों को गरीबी के दलदल में धकेलते हुए जरूरी चिकित्सा से वंचित किया है। इस मर्ज की रग पर हाथ रखते हुए भागवत द्वारा दी गई चेतावनी सत्ताधीशों की आंख खोलने वाली है।

भारत में स्वास्थ्य-शिक्षा को प्रारंभ से ही सामाजिक दायित्व मानने की परंपरा रही है। लेकिन दुर्भाग्य से आज स्कूल-कॉलेज और अस्पताल लाभ संचालित उपक्रमों में तब्दील हो गए हैं और सेवा की बजाय धन कमाने के अड्डे बन गये हैं। आज निजी क्षेत्र के साथ-साथ सरकारों की मानसिकता भी धन-केन्द्रित होती जा रही है, जिससे आमजन को सस्ते एवं किफायती शिक्षा एवं चिकित्सा के साधन-सुविधाएं सुलभ नहीं हो रही है। मुनाफाखोरी की अंतहीन लिप्सा ने कथित गुणवत्ता वाले स्कूलों व अस्पतालों को आम आदमी की पहुंच से दूर किया है। इन जटिल होती स्थितियों के बीच भागवत का यह बयान केवल एक सामान्य टिप्पणी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है-सरकार, नीति-निमार्ताओं और समाज के लिए। शिक्षा और स्वास्थ्य, दोनों ही मानव जीवन के मूलभूत स्तंभ हैं। लेकिन आज इन दोनों क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती व्यावसायिक प्रवृत्तियां इन्हें सेवा के बजाय मुनाफे की मशीन बना रही हैं। निजी स्कूलों की भारी फीस, कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा और महंगे मेडिकल कॉलेजों की ट्यूशन-इन सबने शिक्षा को गरीब और मध्यम वर्ग की पहुंच से दूर कर दिया है। इसी तरह, अस्पतालों और दवा कंपनियों का अत्यधिक मुनाफा-उन्मुख मॉडल स्वास्थ्य को एक महंगे उत्पाद में बदल रहा है। निस्संदेह, मोहन भागवत की यह चिंता हमारे समय की विसंगतियों एवं विकृत आर्थिक सोच पर तीखा प्रहार करती है। आज आम भारतीय परिवारों पर स्वास्थ्य सेवाओं का भारी वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। विडंबना यह है कि इस खर्च का छोटा हिस्सा ही सरकारी खजाने से वहन किया जाता है, जो कि स्वास्थ्य खर्च का महज 17 फीसदी है। वहीं करीब 82 फीसदी स्वास्थ्य खर्च लोगों को मुश्किल हालात में वहन करना पड़ता है। इन स्थितियों के चलते अस्पताल में भर्ती होने के बाद कई परिवार जीवन भर के लिये कर्ज में डूब जाते हैं। तो कई परिवार हमेशा के लिये गरीबी की दलदल में धंस

जाते हैं। आज देश की बड़ी आबादी गैर संक्रामक रोगों, मसलन हृदय रोग, मधुमेह व उच्च रक्तचाप आदि से जूझ रही है। इनकी जांच, चिकित्सकीय परामर्श और उपचार के लिये मरीजों को एक बड़ी रकम चुकाने को मजबूर होना पड़ता है। जो कि बीमा योजनाओं के द्वारा बमुश्किल ही पूरी की जाती है। इन विडम्बनापूर्ण एवं चिन्ताजनक स्थितियों के बीच मोहन भागवत का यह संदेश न केवल आर्थिक सुधार का आान है, बल्कि सामाजिक पुनर्जागरण का भी। शिक्षा और चिकित्सा को व्यापार से मुक्त करना सिर्फ भावनात्मक या नैतिक मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्र की स्थिरता और समानता का प्रश्न है। जब गरीब को इलाज न मिले, और होनहार छात्र को शिक्षा से वंचित रहना पड़े, तब असमानता, असंतोष और सामाजिक अशांति बढ़ती है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नया भारत, विकसित भारत, विश्वासभरा भारत का नारा कोरा दिखावा ही प्रतीत होता है।

नये भारत में जब आम जनता से करो के रूप में भारी भरकम रकम वसूली जा रही है, जो उस रकम को जनकल्याण एवं जनसेवा में खर्च किया जाना चाहिए। आजादी के बाद से सरकार पर शिक्षा एवं चिकित्सा की ही जिम्मेदारी डाली गयी थी, जिसको सरकारों ने बड़ी चतुराई से धीरे-धीरे निःशुल्क की बजाय सशुल्क करने की कारगरी दिखाई है, जो जनता के विश्वास को आहत करने वाली है। इसलिये भागवत का यह बयान सरकार के लिए आंख खोलने वाला होना चाहिए। नीति-स्तर पर ऐसे कदम जरूरी हैं जिनसे-सरकारी शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थानों को उच्च गुणवत्ता के साथ सशक्त एवं जनसुलभ किया जाए। निजी क्षेत्र में फीस और इलाज की दरों पर प्रभावी नियंत्रण हो। सेवा-भाव को बढ़ाने के लिए कर-छूट और प्रोत्साहन मिलें, जबकि मुनाफाखोरी पर कठोर दंड लागू हो। स्वास्थ्य और शिक्षा में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ लागू किया जाए, इन दोनों क्षेत्रों से धन कमाने की प्रवृत्तियों को अपराध माना चाहिए। यह भी तय किया जाये कि इन दोनों क्षेत्रों में सेवा एवं मिशन भावना से आने वालों को ही मान्य किया जाये, धन कमाने वालों के लिये इन दोनों क्षेत्रों के दरवाजे बन्द हो।

शिक्षा और स्वास्थ्य में मुनाफाखोरी को रोकना केवल कानून से संभव नहीं, इसके लिए समाज में मूल्य-आधारित सोच का विकास भी आवश्यक है। सेवा-भाव, मानवीय संवेदनशीलता और न्यायपूर्ण मूल्याधारित आर्थिक ढांचा-यही स्थायी समाधान हैं। मोहन भागवत की यह पहल यदि नीतिगत बदलावों में परिणत होती है, तो यह भारत को न केवल आर्थिक दृष्टि से, बल्कि नैतिक दृष्टि से भी मजबूत बनाएगी। भागवत ने कॉर्पोरेट शैली के कथित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सीएसआर के जुमले के बजाय लोककल्याण के धार्मिक सिद्धांतों के अनुसरण की भी अपील की। वर्तमान में कॉर्पोरेट जगत ने सीएसआर फण्ड को स्वयं के बनाये ट्रस्टों में दिखाकर सरकार के सीएसआर प्रावधानों की धज्जियां उडा रखी है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोच और दर्शन में शिक्षा और चिकित्सा हमेशा सेवा और संस्कार के मूल्यों से जुड़ी रही है। संघ मानता है कि राष्ट्र निर्माण का असली आधार स्वस्थ और शिक्षित नागरिक हैं, और इन दोनों आवश्यकताओं को समाज के हर वर्ग तक सस्ती, सुलभ और समान रूप से पहुंचाना ही सच्ची देशभक्ति है। डॉक्टर को केवल इलाज का शुल्क लेने वाला पेशेवर नहीं, बल्कि रोगी की पीड़ा का साझेदार मानना और शिक्षक को केवल पाठ पढ़ाने वाला कर्मी नहीं, बल्कि जीवन-निमार्ता के रूप में देखना-यही संघ का दृष्टिकोण है। इसी सोच के तहत भागवत का यह आान है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को मुनाफाखोरी के पंजे से मुक्त कर, इन्हें सेवा के आदर्श पर स्थापित किया जाए, ताकि कोई भी बच्चा गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित न हो और कोई भी रोगी आर्थिक बोझ के कारण इलाज से दूर न रहे। सरस्वती के मंदिर एवं सेवा के आश्रय-स्थल आज व्यापार के केंद्र बन गये हैं, ये मिशन नहीं, व्यवसाय बन गये हैं। पिछले दिनों इससे जुड़ा जनाक्रोश तब चरम पर नजर आया जब हैदराबाद के एक स्कूल में नर्सरी में दाखिले की सालाना फीस ढाई लाख रुपये बतायी गई। जिससे अभिभावकों में भारी रोष व्याप्त हो गया। जिसके बाद महंगी होती शिक्षा को लेकर नई बहस छिड़ गई। निस्संदेह, बढ़ती फीस के ये आंकड़े शिक्षा के बढ़ते व्यवसायीकरण एवं बाजारीकरण को भी रेखांकित करते हैं। ऐसे में भागवत की हालिया अपील सत्ताधीशों को नीतिगत बदलावों के बारे में सोचने को विवश कर सकती है, अब समय आ गया है कि सरकार शिक्षा एवं चिकित्सा को लेकर नीतिगत कठोर मानवतापूर्ण बदलाव करें एवं इन्हें मुनाफा कमाने की मशीन न बनने दे। निस्संदेह, भागवत के संदेश पर मोदी सरकार को गंभीरता से विचार-विमर्श करना चाहिए। दरअसल, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा को बाजार की वस्तु के बजाय नागरिक अधिकारों के दायरे में लाने की जरूरत है। इन क्षेत्रों को राजस्व स्रोत के बजाय नागरिक दायित्वों के रूप में मानकर सरकार समता, संतुलन एवं सेवा का समाज स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है।

आखिर कितना उपयोगी साबित होगा ओपन बुक असेसमेंट

सुनील कुमार महला

आज हम इक्कीसवीं सदी में सांस ले रहे हैं और इस सदी की आवश्यकताओं के मद्देनजर हमारे देश में नई शिक्षा नीति-2025 भी लागू की गई है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का ही एक उन्नत रूप या संस्करण है, लेकिन इसमें भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, लचीला और कौशल आधारित(स्किल बेस्ड) बनाने पर जोर दिया गया है।नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2025 की प्रमुख विशेषताओं की यदि हम यहां पर बात करें तो इसमें क्रमशः संरचनात्मक बदलाव(5+3+3+4 मॉडल) किया गया है। वहीं पर दूसरी ओर इसमें कक्षा 5 तक की शिक्षा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में दिए जाने, व्यावसायिक व कौशल शिक्षा(आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता, संचार और सहयोग जैसे कौशल), बहु-विषयक शिक्षा जैसे कि विज्ञान, कला, वाणिज्य के पारंपरिक सीमाओं से हटकर, छात्र अपने रुचि के अनुसार विषय चुनना (उदाहरण के तौर पर गणित के साथ संगीत, भौतिकी के साथ इतिहास आदि), परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली में सुधार, डिजिटल और तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा में सुधार (विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता, अधिक अनुसंधान और वैश्विक सहयोग का अवसर प्रदान करना), तथा समावेशी और समरस शिक्षा को भी शामिल किया गया है।इसी क्रम में हाल ही में, सीबीएसई ने एक साहसिक निर्णय लिया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार अगले शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 9 के विद्यार्थियों को ह्यओपन बुक असेसमेंटह्न (ओबीए) के तहत प्रमुख विषयों में खुली किताब लेकर परीक्षा देने की अनुमति होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो साल में दो बार परीक्षा के साथ-साथ अब 9वीं की परीक्षा को ओपन बुक कर दिया गया है।राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार, ओपन बुक असेसमेंट वह परीक्षा है जिसमें छात्र प्रश्नों के उत्तर देते समय पाठ्यपुस्तक, कक्षा नोट्स, पुस्तकालय की पुस्तकें जैसी संदर्भ सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। वास्तव में सीबीएसई इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को कम करना(टू रिड्यूस टेंडेंसी आफ क्रेमिंग इन स्टूडेंट्स) और योग्यता-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना है। दरअसल, इस संबंध में बोर्ड का यह मानना है कि इससे बच्चों में परीक्षा के प्रति तनाव घटेगा, छात्रों की वैचारिक समझ मजबूत होगी और ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग बढ़ेगा। यहां पाठकों को बताता चलूं कि यह प्रस्ताव दिसंबर 2023 में स्वीकृत एक पायलट प्रोजेक्ट के बाद आया है, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक ओपन-बुक परीक्षाओं का परीक्षण किया गया था, जिसमें छात्रों का प्रदर्शन 12 प्रतिशत से 47 प्रतिशत के बीच रहा। वास्तव में यह संसाधनों के प्रभावी उपयोग और विषय अवधारणाओं को समझने में चुनौतियों का संकेत देता है। गौरतलब है कि सीबीएसई का यह ओपन-बुक असेसमेंट फॉर्मेट भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे मुख्य विषयों को कवर करेगा। एग्जाम के दौरान छात्र टेक्स्ट बुक, क्लास नोट्स और अन्य स्वीकृत रिसोर्सेज का संदर्भ ले सकते हैं। सीबीएसई ने कहा है कि ये स्कूलों पर निर्भर करता है कि इस फॉर्मेट को अपनाना है नहीं, ये बिल्कुल ऑप्शन होगा।असेसमेंट हर शैक्षणिक सत्र में होने वाली तीन पेन-पेपर टेस्ट का हिस्सा होगा।इस संबंध में सीबीएसई ने बताया है कि ये परीक्षा दूसरी बार वाली परीक्षा स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शनल होगी। दूसरे चरण की परीक्षाएं विशेष रूप से सुधार के लिए होंगी। बहरहाल, कहना गलत नहीं होगा कि सीबीएसई के इस फैसले के दूरगामी प्रभावों पर शिक्षा जगत में एक गंभीर बहस छिड़ गई है। सवाल यह उठता है कि क्या सीबीएसई यह प्रयोग वास्तव में हमारे बच्चों को सशक्त बनाएगा या उन्हें आत्मनिर्भरता और स्मरण

शक्ति से दूर ले जाएगा हाल फिलहाल, सीबीएसई का यह मानना है कि यह बदलाव छात्रों के मानसिक दबाव को कम करेगा, खासकर उन विषयों में जहां तथ्यों की मात्रा या संख्या अधिक है। सीबीएसई के इस बदलाव से छात्रों में समस्या समाधान कौशल विकसित हो सकेगा। बोर्ड का यह दावा है कि सैंपल पेपर और प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से छात्रों को संदर्भ सामग्री का सही उपयोग सिखाया जाएगा। साथ ही, स्कूलों को इस पद्धति को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, हालांकि इसे अनिवार्य नहीं किया गया है, जैसा कि इस संदर्भ में ऊपर जानकारी दी जा चुकी है।हाल फिलहाल,देखा जाए तो इस पद्धति के खतरे भी कुछ कम नहीं हैं। इससे आत्मनिर्भरता में कमी आएगी। कहना गलत नहीं होगा कि नौवीं कक्षा वह आधारभूत स्तर है, जहां छात्रों को विषयों की गहराई में जाने, तथ्यों को याद रखने और तर्कशक्ति विकसित करने की आदत डाली जानी चाहिए। यह नई व्यवस्था बोर्ड परीक्षा की तैयारी पर अवश्य ही असर डालेगी, जैसा कि कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। कहना गलत नहीं होगा कि सीबीएसई के कक्षा नौवीं में इस बदलाव से छात्र ह्यओपन बुक असेसमेंट'(ओबीए) के आदी हो जाएंगे और अगली कक्षा यानी कि बोर्ड की दसवीं की परीक्षा में कहीं न कहीं कठिनाइयों को महसूस करेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता पर भी इससे व्यापक असर पड़ेगा। परिणामस्वरूप, बोर्ड परीक्षाओं का औसत परिणाम गिर सकता है, जो सीधे देश की शिक्षा गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। यहां पाठकों को बताता चलूं कि अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों में ओपन बुक परीक्षा पद्धति पहले से प्रचलित है, लेकिन वहां यह केवल उच्च शिक्षा स्तर (कॉलेज और यूनिवर्सिटी) में ही लागू होती है, जहां छात्र परिपक्व, शोधोन्मुख और विश्लेषणात्मक सोच में दक्ष होते हैं। नीदरलैंड की ज्यादातर यूनिवर्सिटीज, सिंगापुर और हांगकांग के कई संस्थान, और कनाडा के कुछ राज्यों में हाईस्कूल स्तर तक यह सिस्टम अपनाया जाता रहा है।कहना गलत नहीं होगा कि स्कूली स्तर पर, खासकर 14-15 साल के किशोरों में, यह पद्धति(ओबीए) अनुशासन और स्मरण शक्ति के विकास में बाधा डाल सकती है। यह ठीक है कि आज भारत में स्कूली स्तर पर बच्चों में रटने की प्रवृत्ति कहीं अधिक है लेकिन इस प्रवृत्ति को कम करने के लिए समझ पर ध्यान केंद्रित करना, विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करना, और एक संरचित अध्ययन कार्यक्रम बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वास्तव में सीबीएसई का उद्देश्य रटने की प्रवृत्ति को कम करना है, तो इसे धीरे-धीरे और वैकल्पिक रूप में लागू किया जाना चाहिए। अमेरिका और यूरोप की भांति इसे देश में पहले उच्च कक्षाओं में प्रयोगात्मक तौर पर शुरू किया जाए।कक्षा 9 में ओबीए के बजाय प्रोजेक्ट-आधारित मूल्यांकन, केस स्टडी और मौखिक परीक्षा जैसे तरीकों को बढ़ावा दिया जा सकता है।सच तो यह है कि व्यावहारिक गतिविधियाँ, समस्या-समाधान अभ्यास, और इंटरैक्टिव शिक्षण अनुभव, 9 वीं कक्षा के छात्रों के उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। वास्तव में, आज जरूरत इस बात की है कि हम छात्रों में संदर्भ सामग्री का सही इस्तेमाल सिखाने के साथ-साथ बिना किताब के उत्तर देने की क्षमताएं भी विकसित करें।

सच तो यह है कि छात्र-छात्राएं मानसिक रूप से सशक्त होने चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता और स्तर को बनाए रखने के लिए संतुलित, चरणबद्ध और परीक्षण-आधारित दृष्टिकोण को अपनाया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। बहरहाल, पाठकों को यहां बताता चलूं कि परीक्षा प्रणाली में ऐसा नवाचार सीबीएसई ने पहली बार नहीं किया है। करीब आठ-दस साल पहले भी ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट (ओटीबीए) भी कमोबेश इसी तरह का था, जिसमें नौवीं व ग्यारहवीं कक्षा के कुछ विषयों में विद्यार्थियों को संदर्भ सामग्री चार माह पहले ही दे दी जाती थी। लेकिन, दो-तीन साल बाद ही इसे हटा दिया गया था। ओपन बुक असेसमेंट का नुकसान यह है कि बिना तैयारी के किताब साथ होने का कोई फायदा नहीं है। साथ ही, किताब से जवाब ढूंढना और फिर समझकर लिखना काफी समय ले सकता है। इतना ही नहीं, अलग-अलग छात्रों की भाषा और प्रस्तुति अलग होगी, जिससे मार्किंग में भी चुनौती आ सकती है। वास्तव में, ओपन बुक परीक्षा को एक के बाद आगे की दूसरी कक्षा में साल-दर-साल लागू किया जाना चाहिए। होना तो यह भी चाहिए कि भले ही शिक्षा प्रणाली में कोई भी प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएं, लेकिन उनको लागू करने से पहले उस प्रणाली के गुण-दोषों के बारे में भली प्रकार आकलन करके ही उन्हें लागू किया जाना चाहिए।देश की शिक्षा के नीति नियंताओं को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ओपन बुक एसेसमेंट का नवाचार पुराने कई प्रयोगों की तरह फाइलों में बंद होकर नहीं रह जाए। सीबीएसई ही नहीं, राज्यों के शैक्षिक मंडलों के भी कई प्रयोग विफल हुए हैं। कभी पांचवी आठवीं में परीक्षा बोर्ड बन जाता है, तो कभी हट जाता है। ऐसी चिंता व विफलता की आशंका नए मॉडल में न रहे, यह सुनिश्चित करना होगा।

लड़की की मौत और हमारी घातक धारणाएँ

डॉ. प्रियंका सौरभ

लड़की अगर घर से लापता हुई है तो वह भागी ही होगी – यह सोच केवल पुलिस की नहीं, बल्कि पूरे समाज की है। यही सोच एक लड़की की जान ले गई। जिस पुलिस को तुरंत उसकी तलाश करनी चाहिए थी, उसने मान लिया कि वह कहीं प्रेम प्रसंग के चलते भाग गई होगी। परिणाम यह हुआ कि अपराधियों को मौका मिल गया और एक मासूम ज़िंदगी समाप्त कर दी गई।

आज सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि बेटियों के लापता होने की शिकायत पर पुलिस की पहली प्रतिक्रिया भाग गई होगी और समाज की पहली प्रतिक्रिया किसके साथ भागी होगी होती है। दोनों ही स्थितियाँ अपराधियों के लिए ढाल बन जाती हैं। पुलिस थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले परिवारों को अक्सर यही सुनने को मिलता है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, लड़की खुद लौट आएगी। यानी शुरूआत से ही मामले को हल्का समझा जाता है। जब तक पुलिस सक्रिय होती है, तब तक कई बार अपराधी अपने मंसूबे पूरे कर चुके होते हैं। यह रवैया केवल लापरवाही नहीं, बल्कि जीवन के साथ खिलवाड़ है।

यह मान लेना कि हर लापता लड़की प्रेम-प्रसंग में भागी है, पुलिस की सोच का सबसे खतरनाक पहलू है। इससे अपराधियों को समय मिल जाता है और पीड़ित परिवार अपने ही समाज की तानों और शक की निगाहों का शिकार बनता है। हमारे गाँव, कस्बों और शहरों में जब भी कोई लड़की लापता होती है, तो अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। लोग यह सोचने की बजाय कि वह कहीं अपराध की शिकार न हो गई हो, यह अनुमान लगाने लगते हैं कि वह किसके साथ भागी होगी। इस सोच से दोहरी चोट लगती है। एक ओर लड़की की इज्जत को बेवजह बदनाम किया जाता है और दूसरी ओर परिवार सामाजिक कलंक से टूटने लगता है।

समाज को यह समझना होगा कि हर लड़की की सुरक्षा पूरे समुदाय की ज़िम्मेदारी है। किसी की अनुपस्थिति पर अफवाह फैलाना या दोषारोपण करना न केवल अमानवीय है, बल्कि अपराध को बढ़ावा देने वाला भी है। एक लड़की की मौत केवल एक परिवार का दुख नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता का आईना है। पुलिस ने समय रहते खोजबीन की होती तो शायद वह आज ज़िंदा होती। समाज ने अफवाहों की बजाय संवेदनशीलता दिखाई होती तो परिवार को न्याय की लड़ाई में अकेला न रहना पड़ता। अब वह लड़की वापस नहीं आ सकती। लेकिन यह जरूरी है कि उसके हत्यारों को सख़्त सजा मिले और आने वाले समय में ऐसी त्रासदियाँ दोहराई न जाएँ।

आज पुलिस बल की सबसे बड़ी समस्या संसाधनों की कमी और प्राथमिकताओं की गड़बड़ी है। नेताओं की सुरक्षा में सैकड़ों जवान तैनात रहते हैं, जबकि थानों और चौकियों में फोर्स की कमी है। नतीजा यह होता है कि आम जनता की शिकायतों पर या तो देर से कार्रवाई होती है या बिल्कुल ही उपेक्षा कर दी जाती है। जरूरत है कि सरकार नेताओं को दिखावटी सुरक्षा देना बंद करे और हर थाने को पर्याप्त पुलिस बल मुहैया कराए। बेटियों से जुड़े मामलों में फास्ट रिस्पॉन्स सिस्टम लागू हो और जिलों के एसपी से मुख्यमंत्री रोजाना सुरक्षा व्यवस्था का फीडबैक लें। जब तक सरकार प्राथमिकताओं में बदलाव नहीं लाएगी, तब तक बेटियाँ असुरक्षित रहेंगी और अपराधियों के हौसले बुलंद रहेंगे।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ताजा रिपोर्ट इस संकट की गम्भीरता को और भी स्पष्ट करती है। वर्ष 2023 के आँकड़ों के अनुसार भारत में प्रतिदिन लगभग 90 महिलाएँ और लड़कियाँ लापता होती हैं। इनमें से कई कभी वापस नहीं लौट पातीं। वहीं हर साल हजारों मामले ऐसे दर्ज होते हैं जिनमें लापता लड़की हत्या, तस्करी या यौन शोषण का शिकार पाई जाती है। इसके बावजूद पुलिस थानों में पहला रवैया यही रहता है कि भाग गई होगी। यदि गुमशुदगी को शुरूआती चरण में ही गंभीर अपराध मानकर खोजबीन की जाए, तो इनमें से कई जानें बचाई जा सकती हैं। लेकिन हमारी सोच और व्यवस्था दोनों इस दिशा में बेहद ढीली और उदासीन हैं।

धारणा बदलना आसान काम नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। जिस दिन पुलिस हर लापता लड़की को संभावित पीड़िता मानेगी, उसी दिन अपराधों पर लगाम लगेगी। जिस दिन समाज लड़की के गायब होने पर तानों और गॉसिप की बजाय सहानुभूति दिखाएगा, उसी दिन परिवारों का बोझ हल्का होगा। जिस दिन सरकार सुरक्षा को पॉलिटिकल शो-ऑफ की बजाय पब्लिक राइट मानेगी, उसी दिन व्यवस्था सुधरेगी। आज हम नारे लगाते हैं– बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। लेकिन जब कोई बेटी लापता होती है, तो हमारी सोच नारे से उलट साबित होती है।

ट्रंप की पूर्व वकील अलीना हब्बा के न्यूजर्सी के अमेरिकी अटॉर्नी के रूप में काम करने पर जज ने उठाया सवाल

एजेंसी
वाशिंगटन (अमेरिका)। पेन्सिलवेनिया के मध्य जिले के न्यायाधीश मैथ्यू डब्ल्यू. ब्रैन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप की पूर्व वकील अलीना हब्बा के न्यूजर्सी के अमेरिकी अटॉर्नी के रूप में काम करने पर सवाल उठाया है। न्यायाधीश ब्रैन ने फैसले में कहा, हब्बा ने बिना किसी कानूनी अधिकार के अमेरिकी अटॉर्नी के रूप में काम किया है। वकीलों ने सवाल उठाया था कि क्या ट्रंप की वफादार अलीना हब्बा को न्यूजर्सी में अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय चलाने का कानूनी अधिकार है। इस फैसले से राष्ट्रपति ट्रंप के शीर्ष संघीय अभियोजकों को चुनने के अधिकार पर संभावित रूप से सीमाएं लग सकती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, संघीय न्यायाधीश ने मैथ्यू डब्ल्यू. ब्रैन ने कहा कि हब्बा के बिना किसी कानूनी अधिकार के अमेरिकी अटॉर्नी के रूप में काम करने से राज्य की पहले से ही पंगु संघीय न्यायिक प्रणाली और भी अधिक अव्यवस्थित हो गई है। न्यायाधीश ब्रैन ने लिखा, क्या हब्बा न्यूजर्सी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी के कार्यालय के कार्यों और कर्तव्यों का वैध रूप से पालन कर रही हैं? मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि वह ऐसा नहीं कर रही हैं।

नेपाल में मधेश आंदोलन के दौरान हुए 400 से अधिक पुलिस इनकाउंटर की जांच का आदेश

काठमांडू। नेपाल में लोकतंत्र पुनर्बहाली के बाद शुरू हुए मधेश आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा किए गए 400 से अधिक इनकाउंटर की जांच का आदेश दिया गया है। 9 साल पहले कोर्ट में दायर एक याचिका पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी इनकाउंटर की निष्पक्ष जांच करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों के बेंच ने सन 2006 से लेकर 2015 के बीच मधेश के जिलों में पुलिस द्वारा विशेष सुरक्षा अभियान के नाम पर किए गए इनकाउंटर की जांच करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील रंजन सिंह के द्वारा दायर किए गए रिट पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए के केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो (सीआईबी) से इन सभी इनकाउंटर की जांच करने को कहा है। 2016 में अधिवक्ता सुनील रंजन सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए सरकार के विशेष सुरक्षा योजना के तहत पुलिस द्वारा 400 से अधिक फेक इनकाउंटर कर निर्दोष नागरिकों की हत्या करने का आरोप लगाते हुए इसकी जांच की मांग की थी। अब 9 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोज केसी और हरि फुयाल की बेंच ने सभी घटनाओं की निष्पक्ष जांच का आदेश दिया है।

यूरोपीय संघ और अमेरिका ने 15 प्रतिशत टैरिफ वाले व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया

वाशिंगटन (अमेरिका)/ब्रसेल्स (बेल्जियम)। आखिरकार यूरोपीय संघ और अमेरिका ने 15 प्रतिशत टैरिफ वाले अपने व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे दिया। पिछले महीने यूरोपीय संघ और अमेरिका ने एक टैरिफ समझौते की घोषणा करके व्यापार युद्ध से दूरी बनाई थी। तब यह सिर्फ एक औपचारिक समझौता था। कई हफ्तों से वार्ताकार इसके विवरण पर विचार-विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इसका विस्तृत विवरण दुनिया के सामने साझा किया। द न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार और ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की खबर के अनुसार, इस समझौते तहत अमेरिका को होने वाले अधिकांश यूरोपीय निर्यात पर 15 प्रतिशत की स्पष्ट अधिकतम टैरिफ दर लागू होगी। संयुक्त बयान में दोनों देशों ने यूरोपीय कारों, दवाओं और लकड़ी पर लागू टैरिफ को कम करने पर सहमति व्यक्त की। लेकिन यूरोप के प्रमुख वाइन और स्पिरिट क्षेत्र सहित अन्य प्रमुख निर्यातक शून्य टैरिफ रियायत पाने में विफल रहे और अब उन्हें बढ़ी हुई लागत का बोझ अमेरिकी उपभोक्ताओं पर डालना पड़ रहा है।

पुतिन से मुलाकात के बाद डॉ. जयशंकर ने कहा-दूसरे विश्वयुद्ध के बाद भारत-रूस संबंध दुनिया में सबसे स्थिर

मास्को। भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अहम मुलाकात की।डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के संबंधों की मजबूती के साथ राष्ट्रपति पुतिन की इस साल के अंत में प्रस्तावित भारत यात्रा के विभिन्न पहलुओं को अंतिम रूप देने पर भी चर्चा की। रूस की तीन दिवसीय यात्रा पर यहां पहुंचे डॉ. जयशंकर की पुतिन से यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्रेमलिन में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। इससे पहले एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और प्रथम उप-प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव से भी मुलाकात की। इन मुलाकातों की तस्वीरें डॉ. जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की हैं।

पाकिस्तान के दक्षिणी वजीरिस्तान में गोलीबारी में 11 घायल, बाजौर जिले की मस्जिद में विस्फोट

एजेंसी
इस्लामाबाद (पाकिस्तान)। पाकिस्तान के दक्षिणी वजीरिस्तान जिले की बिरमल तहसील में गुरुवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई भीषण गोलीबारी में एक महिला और कुछ बच्चों समेत कम से कम 11 लोग घायल हो गए। इसके अलावा बाजौर जिले की एक मस्जिद में हुए विस्फोट में 24 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की सूचना है। यह दुर्गम क्षेत्र है। इस वजह से विस्फोट की पुष्टि नहीं हो सकी है। डान अखबार ने सूत्रों के हवाले से खबर में जानकारी दी है कि यह गोलीबारी करमाजी स्टॉप के पास उस समय हुई जब सेना एक प्रमुख आतंकवादी गढ़ पर कब्जा करने के लिए अभियान चला रही थी। सुरक्षा बल उस इलाके में दो नई चौकियां स्थापित करने में कामयाब रहे। गोलीबारी के सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद वाना के

जिला अस्पताल ले जाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पूरे दिन रुक-रुक कर गोलीबारी होती रही। कई घंटों तक परिवार अपने घरों में कैद रहे। गोलीबारी की वजह से वाना-आजम वारसाक रोड दोपहर करीब 1 बजे तक बंद रही। इस वजह से हजारों लोग वाना रुस्तम बाजार नहीं पहुंच पाए। इसके अलावा, बाजौर की नवागई तहसील के सुदूर 'चारमांग क्षेत्र में हुए एक विस्फोट में 24 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की सूचना है। यह भी दावा है कि मारे गए लोगों में कई आतंकवादी भी शामिल हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, पहाड़ी इलाके में स्थित एक मस्जिद में हुए इस विस्फोट में दो दर्जन से अधिक लोग मारे गए। यह दुर्गम क्षेत्र है, इसलिए घटना की तत्काल पुष्टि नहीं हो सकी। बाजौर में इस समय आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सरबकाफ चल रहा है। सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी को जड़ से उखाड़ने के प्रयास के तहत जिले के कुछ हिस्सों को खाली करा लिया है। इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने दोनों घटनाओं पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

अमेरिका से 7000 नेपाली नागरिकों के निर्वासन के फैसले पर संघीय अदालत में मुहर लगाई

एजेंसी
काठमांडू। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने नेपाल के नागरिकों के लिए अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) को समाप्त करने का रास्ता साफ कर दिया है। इसके साथ ही इस सुविधा के तहत अमेरिका में रह रहे 7000 नेपाली नागरिको को अब देश छोड़ना ही होगा। ताजा आदेश के कारण अमेरिका में रहे रहे 7000 नेपाली नागरिकों को अगस्त के अंतिम सप्ताह तक अमेरिका छोड़ कर जाना होगा। पिछले महीने ही, एक निचली अदालत ने तीन देशों नेपाल, निकारागुआ और होंडुरास के लिए टीपीएस रद्द करने के होमलैंड सुरक्षा विभाग के कदम पर नवंबर के मध्य तक रोक लगा दी थी। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इसे ऊपरी अदालत में चुनौती दी थी जिसके बाद यह ताजा फैसला आया है। अमेरिका की अपील न्यायालय के फैसले के अनुसार, जिन लोगों के पास कानूनी दर्जा नहीं है, जैसे कि ग्रीन कार्ड या शरणार्थी का दर्जा, वे टीपीएस लाभ खोने के बाद कानूनी रूप से काम करने के पात्र नहीं होंगे और उन्हें सरकार द्वारा तय समय सीमा के भीतर देश छोड़ कर जाना होगा। पिछले महीने के आदेश से पहले, ट्रम्प प्रशासन ने 5 अगस्त को नेपाल के लिए तथा सितंबर की शुरुआत में निकारागुआ और होंडुरास के नागरिकों के लिए टीपीएस को समाप्त करने का आदेश दिया था अमेरिका की होमलैंड सुरक्षा विभाग ने गुरुवार के अपील न्यायालय के फैसले को महत्वपूर्ण कानूनी जीत बताया। होमलैंड डिपार्टमेंट की सहायक सचिव ट्रिशिया मैक्लेलन ने कहा, यह ट्रम्प प्रशासन, कानून के शासन और अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक और बड़ी कानूनी जीत है। अस्थायी संरक्षित दर्जा हमेशा अस्थायी होता है।

श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे चार घंटे तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार

एजेंसी
कोलंबो (श्रीलंका)। देश के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को आज आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने चार घंटे तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। वे सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोपों पर बयान दर्ज कराने के लिए एजेंसी के दफ्तर पहुंचे थे। यह मामला सितंबर, 2023 में उनकी पत्नी प्रो. मैत्री विक्रमसिंघे के वॉल्वरहैम्प्टन विश्वविद्यालय के स्नातक समारोह में शामिल होने के लिए लंदन की उनकी यात्रा से संबंधित है। वह श्रीलंका के इतिहास में गिरफ्तार होने वाले पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं। डेली मिरर अखबार की खबर के अनुसार आपराधिक जांच विभाग के अधिकारियों का दावा है कि यात्रा और सुरक्षा खर्चों के लिए सरकारी धन का इस्तेमाल किया गया। पूर्व राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने इन आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि उनकी पत्नी ने अपना खर्च खुद वहन किया और किसी भी सार्वजनिक धन का बताया गया है कि पूर्व राष्ट्रपति से चार घंटे तक पूछताछ की गई। इसके बाद उन्हें आज सुबह हिरासत में ले लिया गया। उन्हें आज शाम तक फोर्ट

दुरुपयोग नहीं किया। इससे पहले सीआईडी ने उनकी पूर्व निजी सचिव सैंड्रा परेरा और पूर्व राष्ट्रपति सचिव समन एकनायके के बयान दर्ज किए। बाद में बयानों को फोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर पेश किया। मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जा सकता है। विक्रमसिंघे ने गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे के बाद जुलाई, 2022 में राष्ट्रपति पद संभाला। सितंबर, 2024 में वह चुनाव हार गए।

बलोच लड़ाकों का खुजदार जिले के जेहरी इलाके में कब्जा, सुरक्षा बलों को बनाया निशाना

एजेंसी
क्वेटा (बलोचिस्तान)। सशस्त्र बलोच लड़ाकों ने पिछले 10 दिनों से खुजदार जिले के जेहरी इलाके पर कब्जा कर रखा है। लड़ाकों ने इलाके के गजान, सोहिंदा और सुन्नी में पाकिस्तान के सैन्य बलों को निशाना बनाकर भीषण हमले किए हैं। हमलों में सुरक्षा बलों को नुकसान होने की बात कही जा रही है। पाकिस्तान के अधिकारियों ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। द बलोचिस्तान पोस्ट की खबर के अनुसार बलोच लड़ाकों ने जेहरी पर सशस्त्र कब्जे की शुरुआत 11 अगस्त को जनसभा को संबोधित कर की। इस दौरान शहर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया। बाद में लड़ाकों ने प्रवेश मार्गों को अवरुद्ध कर सैन्य आवाजाही को रोक दिया। यही नहीं सुन्नी-नूरगामा सड़क पर बुलडोजर चलवा दिया। गजान और मश्क से आगे बढ़ रहे सैनिकों पर हमला किया। इस बीच, पाकिस्तान की सेना ने अंजीरा आरसीडी क्रॉस

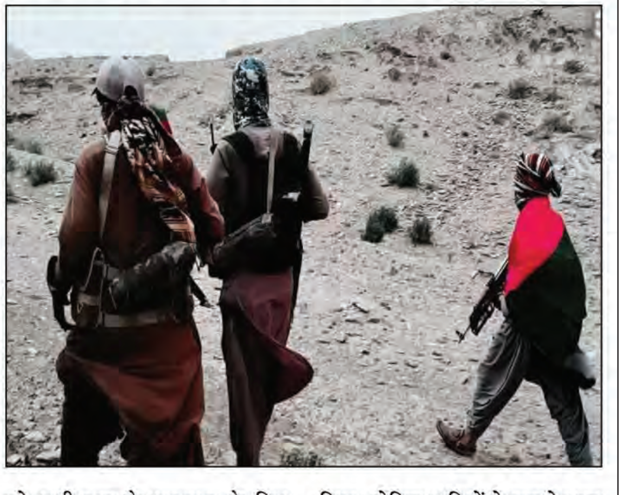

को सभी तरह के यातायात के लिए बंद कर दिया है। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि सैनिकों ने जेहरी जा रहे दो युवकों को कथित तौर पर यातना देने के बाद हिरासत में लेने का प्रयास किया, लेकिन यात्रियों ने हस्तक्षेप कर उन्हें छुड़ा लिया।

दक्षिण अमेरिका के ड्रेक पैसेज में शक्तिशाली भूकंप, यूएसजीएस ने 7.5 तीव्रता बताई

एजेंसी
वाशिंगटन। दक्षिण अमेरिका के ड्रेक पैसेज को शक्तिशाली भूकंप का सामना करना पड़ा। शुरुआत में इसकी तीव्रता 8 बताई गई। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) ने बाद में कहा कि भूकंप की तीव्रता 7.5 रही। भूकंप 10.8 किलोमीटर की गहराई पर आया। इसका केंद्र ड्रेक पैसेज था। द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार यह ड्रेक पैसेज दक्षिण अमेरिका के सबसे दक्षिणी सिरे और अंटार्कटिका के बीच एक जल निकाय है। अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली ने ड्रेक पैसेज भूकंप के बाद कोई चेतावनी जारी नहीं की। प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र (पीटीडब्ल्यूसी) ने जरूर चिली के लिए संक्षिप्त चेतावनी जारी की। इसमें कहा गया कि ड्रेक पैसेज में आए भूकंप से अगले तीन घंटों के भीतर चिली के कुछ तटों पर खतरनाक सुनामी लहरें उठने की आशंका है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप अर्जेंटीना समयानुसार रात 11:16 बजे चिली और अर्जेंटीना

के तटों से छह मील की गहराई पर आया। भनक लगते ही चिली सरकार ने अंटार्कटिका स्थित अपने कुछ ठिकानों पर संभावित सुनामी लहरों की चेतावनी जारी की। राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी केंद्र ने कहा कि अमेरिका में सुनामी का खतरा बहुत कम है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भूकंप की अपनी माप को 8 की प्रारंभिक रीडिंग से घटाकर 7.5 कर दिया।एबीसी न्यूज के अनुसार यह भूकंप अर्जेंटीना के उशुआइया से लगभग 710 किलोमीटर (441 मील) दक्षिण-पूर्व में ड्रेक पैसेज में स्थानीय समयानुसार रात 11:16 बजे आया। भूकंप की प्रारंभिक गहराई 10.8 किलोमीटर (6.7 मील) थी। ड्रेक पैसेज दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे और अंटार्कटिक प्रायद्वीप के बीच दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण प्रशांत महासागरों को जोड़ता है। यह क्षेत्र अत्यंत दुर्गम है। अभी तक किसी प्रकार के नुकसान या किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। एरिन तूफानः द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक अन्य खबर के अनुसार अमेरिका में तूफान एरिन की वजह से उत्तरी कैरोलिना के आउटर बैंक्स में तीव्र लहरें उठ रही हैं। इसके मद्देनजर न्यूयॉर्क शहर प्रशासन ने तैराकी पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ा दी है। न्यूयॉर्क के समुद्र तट को पहले बुधवार और तैराकी के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब यह प्रतिबंध शुक्रवार को भी जारी रहेंगे। एरिन तूफान उत्तरी कैरोलिना के आउटर बैंक्स से लगभग 285 मील पूर्व में स्थित है और अटलांटिक महासागर के माध्यम से उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ रहा है। आउटर बैंक्स में ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की गई है।

अमेरिका के पहले सरकारी अप्रवासी हिरासत केंद्र को जज ने दिया ढहाने का आदेश, ट्रंप प्रशासन फैसले के खिलाफ करेगा अपील

एजेंसी
वाशिंगटन। अमेरिका के मियामी स्थित संघीय जिला न्यायालय की न्यायाधीश कैथलीन एम. विलियम्स ने आदेश दिया कि अप्रवासी बंदियों की हिरासत के लिए बनाए गए देश के पहले सरकारी केंद्र (फ्लोरिडा एवरग्लेड्स स्थित हिरासत केंद्र) का अधिकांश हिस्सा दो माह में ध्वस्त कर दिया जाए। साथ ही इस केंद्र में कोई नया बंदी भी न भेजा जाए। ट्रंप प्रशासन ने फैसले को चुनौती देने की घोषणा की है। इस केंद्र को आव्रजन निरोध केंद्र और एलीगेटर अल्काट्राज के नाम से भी जाना जाता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, न्यायाधीश कैथलीन एम. विलियम्स ने फैसले में राज्य और संघीय सरकारों को एलीगेटर अल्काट्राज नामक इस केंद्र के निर्माण से पहले संभावित पर्यावरणीय क्षति पर विचार न करने के लिए फटकार भी लगाई है। उन्होंने सरकार के दोनों विभागों को मौजूदा बंदियों को हटाने और बाड़, प्रकाश व्यवस्था, बिजली जनरेटर और अन्य सामग्री हटाने के लिए 60 दिन का समय दिया है। आदेश में उस स्थान पर किसी भी नए निर्माण पर भी रोक लगाई गई है। न्यायाधीश कैथलीन एम. विलियम्स का मानना है कि राज्य और संघीय सरकारों ने निर्माण परियोजना से पहले पर्यावरणीय समीक्षा न कर संघीय कानून का उल्लंघन किया है। न्यायाधीश विलियम्स ने पर्यावरणविदों और मिकोसुकी जनजाति के सदस्यों के आग्रह को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि यह केंद्र संरक्षित भूमि से घिरा हुआ है। यह संवेदनशील एवरग्लेड्स पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है।

कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कांग्रेसी जिलों के पुनर्सीमांकन संबंधी दो विधेयकों पर हस्ताक्षर किए

एजेंसी
सैक्रामेंटो (कैलिफोर्निया) अमेरिका। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने कांग्रेसी जिलों के पुनर्सीमांकन संबंधी दो विधेयकों पर हस्ताक्षर कर दिए। विधानमंडल ने दोनों विधेयक पारित कर उनके पास भेजे थे। कैलिफोर्निया का यह कदम ज्यादा डेमोक्रेट्स को चुनने की व्यापक योजना का हिस्सा है।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप के आग्रह पर बुधवार को टेक्सास में रिपब्लिकन बहुमत वाली विधानसभा में पारित किए गए पुनर्सीमांकन मानचित्र का तत्कालिक जवाब है। कैलिफोर्निया और टेक्सास के इस घटनाक्रम का प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर पड़ना तय है। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन लंबे समय से प्रतिनिधि सभा पर नियंत्रण के लिए प्रयासरत है । ये कदम संभावित राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार न्यूसम को मध्यावधि चुनाव चक्र में

राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे खड़ा कर देने वाला है। न्यूसम ने विधेयकों पर हस्ताक्षर करने से पहले कहा, हम टेक्सास में जो हुआ, उसका जवाब दे रहे हैं। हम जो कुछ हुआ उसे बेअसर कर रहे हैं और हम अमेरिकी लोगों को एक उचित मौका दे रहे हैं, क्योंकि जब सभी चीजें समान होती हैं, तो हम सभी एक ही नियमों से खेलते हैं। चुनाव विश्लेषकों का कहना है कि राज्य आमतौर पर प्रत्येक जनगणना के बाद जनसंख्या परिवर्तन को दर्शाने के लिए कांग्रेसी जिलों में बदलाव करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने टेक्सास में रिपब्लिकन के माध्यम से ऐसाकर परंपरा को तोड़ दिया है। इससे दो सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ना स्वाभाविक है। कैलिफोर्निया के डेमोक्रेटिक असेंबलीमैन मार्क बर्मन ने स्टेट कैपिटल में विधेयक पेश करते हुए कहा, हम यह लड़ाई नहीं चाहते हैं और हमने यह लड़ाई नहीं चुनी है, लेकिन लोकतंत्र को खतरे में डालते हुए हम इस लड़ाई से भाग नहीं सकते और न ही भागेंगे। देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य होने के नाते कैलिफोर्निया में किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे अधिक अमेरिकी प्रतिनिधि हैं। इनकी संख्या 52 है। इनमें से 43 सीटें डेमोक्रेट और नौ रिपब्लिकन के पास हैं। यह बड़ा दलगत विभाजन है।

ओली सरकार के संसद में विश्वास मत हासिल न करने के मामले में सुनवाई करेगा नेपाल सुप्रीम कोर्ट

एजेंसी
काठमांडू। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार को समर्थन देने वाले दो दलों के समर्थन वापस लेने के बाद भी संवैधानिक प्रावधानों के तहत सदन में विश्वास का मत नहीं लेने के मामले में आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार से नागरिक उन्मुक्ति पार्टी और जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ने 45 दिन पहले ही अपना समर्थन वापस ले लिया था। इनमें नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकार में शामिल थी तो जनता समाजवादी पार्टी बाहर से समर्थन दे रही थी। नेपाल के संविधान में प्रावधान है कि यदि सरकार में शामिल कोई दल समर्थन वापस लेता है तो ऐसे में प्रधानमंत्री को 30 दिन के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना होगा, लेकिन 45 दिन के बाद भी ऐसा न होने पर उच्चतम

न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिस आज सुनवाई शुरू हो रही है।

यूएमएल पार्टी के महासचिव शंकर पोखरेल ने कहा कि सरकार बनाने का दावा पेश करते समय सिर्फ नेपाली कांग्रेस और यूएमएल पार्टी के समर्थन से सरकार का गठन किए जाने का पत्र दिया गया था इसलिए बाकी दलों के समर्थन देने या वापस लेने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता वीरेन्द्र केसी का तर्क है कि नेपाल के संविधान में प्रावधान है कि जब सरकार में शैल कोई दल सरकार से बाहर हो जाता है या समर्थन वापस ले लेता है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री को 30 दिनों के भीतर ही सदन में विश्वास मत लेना होगा।

ब्रिटेन ने ईरानी तेल कारोबारी और चार कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध

एजेंसी
लंदन। ब्रिटेन ने ईरानी तेल कारोबारी मोहम्मद हुसैन शमखानी और चार कंपनियों पर तेहरान की विदेशी गतिविधियों को समर्थन देने वाले नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप लगाते हुए प्रतिबंध लगाया है। इनमें यूक्रेन और इजराइल में अस्थिरता फैलाना भी शामिल है। ब्रिटिश विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन प्रतिबंधों में शमखानी पर संपत्ति फ्रीज और यात्रा प्रतिबंध तथा शिपिंग, पेट्रोकेमिकल और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों पर संपत्ति फ्रीज शामिल है। ब्रिटेन के मध्य पूर्व मामलों के मंत्री हैमिश फाल्कनर ने कहा, ईरान की व्यापारिक नेटवर्क और संबद्ध संगठनों से होने वाली आमदनी उसे अस्थिर करने वाली गतिविधियों को अंजाम देने, क्षेत्रीय प्रॉक्सी और साझेदारों को समर्थन देने और ब्रिटेन में राज्य-प्रायोजित खतरों को सक्षम करने में मदद करती है। ईरानी दूतावास ने इन प्रतिबंधों को एकतरफा और अवैध कदम बताते हुए खारिज किया और इसे निराधार आरोप करार दिया। शमखानी, जो ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के सलाहकार के बेटे हैं, से टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका। अमेरिका ने पिछले महीने ही शमखानी पर प्रतिबंध लगाए थे, यह आरोप लगाते हुए कि वे एक विशाल नेटवर्क के जरिए कंटेनर शिप और टैंकरों को नियंत्रित करते हैं।

नेपाल के शुक्लाफांटा राष्ट्रीय उद्यान में इस वर्ष मिले 19 दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी

एजेंसी
काठमांडू। नेपाल के शुक्लाफांटा राष्ट्रीय उद्यान में इस वर्ष 19 दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी पाए गए हैं। इन दुर्लभ पक्षियों में छोटी टाइट, सारस, काले पैर वाले ईगल, काले पैर वाले गिद्ध और छोटे भूरे रंग के गिद्ध, सुनहरे गिद्ध, भीमकाय बाज, लुप्तप्राय बाज़, सफेद गले वाले तीतर और कई अन्य प्रजातियां शामिल हैं। शुक्लाफांटा राष्ट्रीय उद्यान 465 दुर्लभ प्रजातियों के पक्षियों का घर है, जिनमें से इस वर्ष 19 को दुनिया भर में दुर्लभ माना गया है। नेपाल की बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी (बीसीएन) के पक्षी विज्ञानी हिरुलाल डगौरा के अनुसार इनमें से सबसे अधिक लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। यह ऐसा पक्षी है, जो घास के मैदानों में रहता है और शुक्लाफांटा की पहचान से निकटता से जुड़ा हुआ है। पार्क में इसकी जनसंख्या बहुत कम है। शुक्लाफांटा के लिए अद्वितीय सुनहरे कैनन पक्षी को लालपानी, मोहनपुर और सिंहपुर जैसे घास के मैदानों में देखा जा सकता है। यह पक्षी आर्द्रभूमि और घास के मैदानों

के पास कांटेदार पेड़ों में घोंसला बनाता है, जिसमें कभी-कभी एक ही पेड़ में दर्जनों घोंसले पाए जाते हैं। इस उद्यान में सफेद गले वाले तीतर जैसे प्रवासी पक्षी सर्दियों में आते हैं, जबकि सारस अक्सर झीलों में आते हैं। इस उद्यान में विभिन्न गिद्ध भी रहते हैं। शुक्लाफांटा गिद्धों की आठ प्रजातियों का घर है, जिनमें से चार सेबल गिद्ध, कम धूसर गिद्ध, सुनहरा गिद्ध और सफेद गिद्ध गंभीर रूप से लुप्तप्राय हैं। डगौरा के अनुसार यहां सेबल गिद्धों की आबादी थोड़ी बढ़ी है, लेकिन अन्य प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। यहां की सभी गिद्ध प्रजातियां प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईयूसीएन) की रेड लिस्ट में सूचीबद्ध हैं। यह उद्यान सर्दियों में प्रवासी पक्षियों के लिए भी एक प्रमुख गंतव्य है।

दुर्लभ जलपक्षी, जैसे काले सिर वाला बतख इस मौसम के दौरान पार्क के तालाबों में जाते हैं। नेपाल की बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी ने हाल ही में एक सर्वेक्षण कराया है, जिसमें शुक्लाफांटा और उसके आसपास की आर्द्रभूमि में लगभग 5,882 जलपक्षी दर्ज किए गए। सर्दियों के दौरान अपने प्रचुर मात्रा में पक्षियों के जीवन के कारण यह उद्यान पक्षियों पर नजर रखने वालों के लिए एक लोकप्रिय स्थान बन गया है। लगभग 305 वर्ग किलोमीटर में फैले शुक्लाफांटा में 71 प्रतिशत वन हैं, जिसमें 80 प्रतिशत से अधिक वन साल के पेड़ों से बने हैं। ये वन और घास के मैदान उद्यान की समृद्ध एवियन विविधता के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करते हैं।

शेयर बाजार में लगातार छठे दिन तेजी, मजबूती के साथ बंद हुए सेंसेक्स और निफ्टी

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार लगातार छठे कारोबारी दिन मजबूती के साथ बंद होने में सफल रहा। आज के कारोबार की शुरुआत भी बढ़त के साथ हुई थी। बाजार खुलते ही बिकवाली का दबाव बन जाने के कारण इसकी चाल में गिरावट आ गई। हालांकि, पहले आधे घंटे के कारोबार के बाद ही खरीदारों ने लिवाली का जोर बना दिया, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों की चाल में तेजी आ गई। हालांकि आज पूरे दिन बाजार में लगातार उतार चढ़ाव होता रहा। राहत की बात यही रही कि बिकवाली का दबाव बनने के बावजूद शेयर बाजार लगातार हरे निशान में ही बना रहा। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 0.17 प्रतिशत और निफ्टी 0.13 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुए। आज दिन भर के कारोबार के दौरान ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में जम कर खरीदारी होती रही। इसी तरह बैंकिंग, आईटी और टेक इंडेक्स भी मजबूती के साथ बंद हुए। दूसरी ओर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, एफएमसीजी और एनर्जी सेक्टर के शेयरों में आज बिकवाली का दबाव बना रहा। इसी तरह कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटोमोबाइल और मेटल इंडेक्स भी गिरावट के साथ बंद हुए।

भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प निर्यात को नए मुकाम तक ले जाने की जरूरतः गिरिराज सिंह

नई दिल्ली। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत के हथकरघा और हस्तशिल्प निर्यात को बढ़ाने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि महिला कारीगरों की मासिक इनकम को कम से कम 15 से 20 हजार रुपये तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने नई दिल्ली के वसंत कुंज में कपड़ा मंत्रालय की तरफ से विकसित शिल्प परिसर 'द कुंज' का उद्घाटन करने के बाद कहा कि देश में करीब एक करोड़ लोग हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सिंह ने कहा कि यह कुंज भवन देशभर के कारीगरों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने में मदद करेगा। हमारा लक्ष्य महिला कारीगरों (शिल्प दीदियों) की आय को कम से कम 15 हजार रुपये से 20 हजार रुपये प्रति माह तक बढ़ाना है। उन्होंने हथकरघा और हस्तशिल्प के निर्यात को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की जरूरत पर प्रकाश डाला। शिल्प परिसर 'कुंज भवन' की परिकल्पना एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक और खुदरा स्थल के रूप में की गई है, जो भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा की विविध विरासत का जश्न मनाने और उसे बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।

जीएसटी के 5 फीसदी और 18 फीसदी स्लैब को जीओएम की मंजूरी, जीएसटी काउंसिल लेगा फैसला

नई दिल्ली। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद के मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने जीएसटी के 5 फीसदी और 18 फीसदी के स्लैब को मंजूरी दे दी है। लग्जरी सामानों को 40 फीसदी के दायरे में लाया जाएगा। इसे जीएसटी काउंसिल के पास भेजा गया है, जो इस पर फैसला लेगी। अभी जीएसटी के चार स्लैब 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी हैं। जीएसटी की दरों को युक्तिसंगत बनाने, बीमा पर कराधान और क्षतिपूर्ति उपकर से संबंधित मंत्री समूह की बैठक के दूसरे दिन जीओएम के संयोजक सम्राट चौधरी ने बताया कि हमने केंद्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है। प्रस्ताव में 12 फीसदी और 28 फीसदी के जीएसटी स्लैब को खत्म करने की बात है। उन्होंने कहा कि सभी ने केंद्र के प्रस्तावों पर अपने सुझाव दिए। हालांकि, कुछ राज्यों ने कुछ आपत्तियां भी जताईं। इसे जीएसटी काउंसिल के पास भेजा गया है, जो इस पर फैसला लेगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से आए प्रस्ताव पर सभी लोगों ने अपनी बात रखी है। जीओएम ने 12 फीसदी और 28 फीसदी टैक्स को समाप्त करने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। मंत्री समूह दो दिन से केंद्र सरकार के 'अगली पीढ़ी' के जीएसटी सुधारों पर विचार कर रहा है।

ओपनएआई भारत में खोलेगा पहला ऑफिस, दिल्ली में होगी शुरुआत

नई दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया की दिग्गज कंपनी ओपनएआई ने भारत में अपना पहला कार्यालय खोलने का ऐलान किया है। यह कार्यालय दिल्ली में स्थापित किया जाएगा, जो कंपनी के लिए भारत में अपनी पहुंच और गतिविधियों को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। ओपनएआई के इस कदम को भारत के तेजी से बढ़ते एआई बाजार और विशाल प्रतिभा पूल का लाभ उठाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। कंपनी भारत सरकार, स्थानीय व्यवसायों, स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं के साथ मिलकर काम करने की योजना बना रही है ताकि देश में एआई के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। इस नए कार्यालय से भारत में एआई इनोवेशन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ओपनएआई भारत के विशिष्ट चुनौतियों और अवसरों के लिए एआई मॉडल विकसित करने पर काम कर सकता है।

वायरस अटैक के कारण सुपारी उत्पादक किसानों को हुए नुकसान की समुचित भरपाई होगीः शिवराज सिंह

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी एवं केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी सहित कर्नाटक के सांसद तथा विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सुपारी उत्पादक किसानों की भलाई और उनकी समस्याओं के समाधान से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों के हित सुरक्षित रहेंगे और वे स्वयं कर्नाटक का दौरा करके स्थिति का जायजा लेंगे। सुपारी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) की रिपोर्ट को लेकर चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि एक रिपोर्ट से कर्नाटक की सुपारी को लेकर कैंसरजन्य होने संबंधी कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि सुपारी को लेकर इस रिपोर्ट से उत्पन्न भ्रांतियों को दूर करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के वैज्ञानिकों की टीम परीक्षण कर रही है। उन्होंने बैठक में टीम को जल्द रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। शिवराज सिंह ने कहा कि भारत में प्राचीन काल से लोग सुपारी खाते आ रहे हैं। हमारे यहां हर मंगल कार्यों में सुपारी का उपयोग होता है। शिवराज सिंह ने कहा कि एरोलिफ जैसी बीमारी, जो सुपारी के वृक्षों को नष्ट कर देती है, उसके नियंत्रण के लिए वैज्ञानिकों की टीम काम कर रही है।

साथ ही, क्लीन प्लांट उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई है। शिवराज सिंह ने कहा कि वायरस के कारण सुपारी के किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के विषय पर भी अधिकारियों को गंभीरता और शीघ्रता से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में सुपारी के अवैध आयात, नमी की समस्या तथा छोटी-बड़ी सुपारी के दामों में अंतर जैसे अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से बातचीत की गई। सभी मुद्दों का समयबद्ध समाधान निकाला जाएगा और किसानों तथा सुपारी से जुड़े सहकारिता क्षेत्र के हित पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने यह भी कहा कि सुपारी एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है, जिसे भारत में सभी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों में स्थान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सुपारी में मौजूद अनेक एल्कलॉइड के कारण इसका उपयोग आयुर्वेदिक और पशु चिकित्सा औषधियों में भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों की टीम के साथ कर्नाटक का दौरा करेंगे और स्थिति का जायजा लेते हुए सुपारी उत्पादन के विकास को लेकर आगे की रूपरेखा तय करेंगे।

लगातार दूसरे दिन डॉलर की तुलना में कमजोर हुआ रुपया, 18 पैसे गिरकर बंद हुई भारतीय मुद्रा

एजेंसी

नई दिल्ली। कच्चे तेल की कीमत में तेजी आने और डॉलर इंडेक्स के मजबूत होने का असर आज भारत के मुद्रा बाजार में साफ नजर आया। इन दोनों वजहों से आज मुद्रा बाजार में नकारात्मक माहौल बन गया। इसके साथ ही मुद्रा बाजार में डॉलर की मांग बढ़ने के कारण भी रुपया आज लगातार दूसरे दिन डॉलर की तुलना में कमजोर होकर बंद हुआ। भारतीय मुद्रा आज डॉलर की तुलना में 18 पैसे फिसल कर 87.26 (अनंतिम) के स्तर पर बंद हुई। इसके पहले पिछले कारोबारी दिन बुधवार को भारतीय मुद्रा 87.08 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुई थी। रुपये ने आज के कारोबार की शुरुआत मजबूती के साथ ही की थी। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भारतीय मुद्रा ने आज सुबह डॉलर के मुकाबले 5 पैसे की बढ़त के साथ 87.03 रुपये के स्तर से कारोबार की शुरुआत की थी। आज का कारोबार शुरू होने के बाद रुपया 16 पैसे की उछाल के साथ 86.92 के स्तर तक पहुंच गया, लेकिन इसके बाद डॉलर की मांग में तेजी आ जाने की वजह से बाजार में नकारात्मक माहौल बन गया। डॉलर की मांग बढ़ते ही रुपया ऊपरी स्तर से 35 पैसा लुढ़क कर 19 पैसे की कमजोरी के साथ 87.27 के स्तर तक पहुंच गया। अंत में दिन भर के कारोबार के बाद डॉलर की तुलना में रुपये ने 18 पैसे की गिरावट के साथ 87.26 के स्तर पर आज के कारोबार का अंत किया। मुद्रा बाजार के आज के कारोबार में रुपये ने डॉलर की तुलना में तो कमजोर प्रदर्शन किया ही, ज्यादातर दूसरी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के मुकाबले भी भारतीय मुद्रा ने कमजोरी दिखाई।

ताप विद्युत संयंत्रों में पर्याप्त कोयला भंडार : जी. किशन रेड्डी

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि बिजली उत्पादन कंपनियों के पास कोयले का पर्याप्त भंडार है, फिलहाल कोयले की कोई कमी नहीं है। जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के 13वें दौर के शुभारंभ के अवसर पर यह बात कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि भारत पिछली नीलामियों की सफलता को आगे बढ़ा रहा है, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा काफी मजबूत हुई है। उन्होंने बताया कि कोयला क्षेत्र को वाणिज्यिक खनन के लिए खोले जाने के बाद से 134 कोयला खदानों की नीलामी की जा चुकी है। रेड्डी ने कहा कि भविष्य में बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के लिए कोयला उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। वाणिज्यिक कोयला खदानों के नीलामी के लॉन्चिंग पर रेड्डी ने अपने संबोधन में कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस के शासनकाल में बिजली आपूर्ति पर औद्योगिक सीमा के कारण तेलंगाना के कारखाना मालिक अक्सर हड़ताल पर चले जाते थे। किसानों को आधी रात को अपने पंपों के पास बिजली के इंतज़ार में जागना पड़ता था। लेकिन 2014 के बाद से, परिवर्तनकारी सुधारों और रिकॉर्ड कोयला उत्पादन के कारण, हर राज्य ने पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की है। कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने अपने संबोधन में कहा कि 13वें वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का शुभारंभ भारत की ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूती देगा। इससे कोयला उत्पादक राज्यों को भारी राजस्व लाभ मिलेगा, स्थानीय समुदायों को रोजगार एवं व्यवसाय के अवसर प्राप्त होंगे और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में कोयला मंत्रालय विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। मंत्रालय ने पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया को सुनिश्चित किया है, जिससे निवेशकों का विश्वास और बढ़ा है। 13वें दौर के वाणिज्यिक कोयला खदान की नीलामी के लॉन्चिंग के अवसर पर कोयला सचिव विक्रम देव दत्त ने अपने संबोधन में कहा कि कोयला भारत की ऊर्जा सुरक्षा का मुख्य आधार बना हुआ है। उन्?होंने कहा कि 2014 के बाद से सुधारों की एक श्रृंखला ने पारदर्शिता को बढ़ाया है, व्यापार करने में आसानी में सुधार किया है, और प्रधानमंत्री द्वारा कल्पना के रूप में सुधारों को अगले स्तर तक ले जाने के लिए मंच निर्धारित किया है।

विक्रम सोलर के 2,079 करोड़ रुपये के आईपीओ को 54.63 गुना अभिदान मिला

एजेंसी

नई दिल्ली। सोलर मॉड्यूल विनिर्माता कंपनी विक्रम सोलर लिमिटेड के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को बोली के अंतिम दिन 54.63 गुना अभिदान मिला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के आंकड़ों के मुताबिक इस आईपीओ को 4,53,61,650 शेयरों की पेशकश के मुकाबले 2,47,81,57,740 शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं। आंकड़ों के अनुसार पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के हिस्से को 142.79 गुना का अभिदान मिला है। गैर-संस्थागत निवेशकों के हिस्से को 50.90 गुना अभिदान मिला, जबकि खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों (आरआईआई) के कोटा को 7.65 गुना अभिदान मिला है। विक्रम सोलर लिमिटेड ने सोमवार को एंकर निवेशकों से 621 करोड़ रुपये जुटाए। कंपनी के 2,079 करोड़ रुपये के आईपीओ का मूल्य दायरा 315-332 रुपये प्रति शेयर है। यह आईपीओ 1,500 करोड़ रुपये तक के नए शेयरों के निर्गम और प्रवर्तकों द्वारा 1.74 करोड़ से अधिक शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) का संयोजन है। विक्रम सोलर लिमिटेड कंपनी ने वर्ष 2009 में 12 मेगावाट की स्थापित सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता के साथ अपना विनिर्माण कार्य शुरू किया था। अब इसकी स्थापित क्षमता बढ़कर 4.50 गीगावाट हो गई है। इसने 19 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए अखिल भारतीय उपस्थिति स्थापित की है। कंपनी के प्रमुख घरेलू ग्राहकों में एनटीपीसी, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन और गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी है।

सर्राफा बाजार में मामूली तेजी, सोना और चांदी की बढ़ी कीमतें

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार में लगातार मामूली तेजी का रुख नजर आ रहा है। कीमत में उछाल आने के कारण आज देश के ज्यादातर सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 1,00,760 रुपये से लेकर 1,00,910 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना भी आज 92,310 रुपये से लेकर 92,460 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। सोना की तरह चांदी के भाव में भी तेजी आने के कारण कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज 1,16,100 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना आज 1,00,910 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 92,460 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

वहीं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,00,760 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 92,310 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,00,810 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 92,360 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 1,00,760 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 92,310 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। कोलकाता में भी 24 कैरेट सोना 1,00,760 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 92,310 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,00,910 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 92,460 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,810 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 92,360 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,00,910 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 92,460 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी आज सोने के भाव में तेजी आई है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना आज 1,00,760 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह इन तीनों शहरों के सर्राफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 92,310 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने इस साल जून में 19.37 लाख नए सदस्य जोड़े

एजेंसी

नई दिल्ली। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने जून महीने में 19.37 लाख नए सदस्य जोड़े हैं। इनमें से 25 वर्ष तक की आयु वर्ग के 9.58 लाख लोग हैं, जो कुल पंजीकरण का 49.50 फीसदी हैं। इस अवधि में महिला सदस्यों का शुद्ध नामांकन 4.13 लाख रहा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि ईएसआईसी की अस्थायी पेरोल आंकड़ों से पता चलता है कि जून में 19.37 लाख नए कर्मचारी जुड़े। इनमें से 25 वर्ष तक की आयु वर्ग के 9.58 लाख लोग हैं जो कुल पंजीकरण का 49.50 फीसदी है। आंकड़ों के मुताबिक जून में महिला सदस्यों का शुद्ध नामांकन 4.13 लाख रहा। इसके अलावा कुल 87 ट्रांसजेंडर कर्मचारी भी ईएसआई योजना के तहत पंजीकृत थे। मंत्रालय ने कहा कि जून में कुल 34,762 नए प्रतिष्ठानों को ईएसआई योजना के सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाया गया है, जिससे अधिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार यह पेरोल आंकड़े अस्थायी हैं, क्योंकि आंकड़े तैयार करना एक सतत प्रक्रिया है।

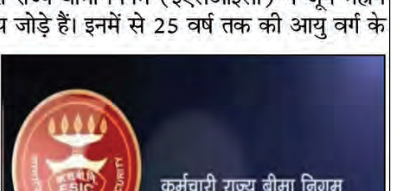

आरबीआई ने महंगाई का लक्ष्य चार फीसदी रखे जाने पर सार्वजनिक राय मांगी

एजेंसी

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने आम लोगों से इस बारे में राय मांगी कि मौद्रिक नीति के लिए खुदरा महंगाई का चार फीसदी का लक्ष्य ही उपयुक्त रहेगा या बदलते वैश्विक-घरेलू परिदृश्य में नए मानदंड तय करने की जरूरत है। रिजर्व बैंक ने विभिन्न पक्षों से इस पर 18 सितंबर, 2025 तक सुझाव आमंत्रित किए हैं।आरबीआई ने एक चर्चा पत्र जारी कर चार प्रमुख सवालों पर राय मांगी है। इसमें प्रमुख सवाल यह है कि मौद्रिक नीति का मार्गदर्शन मुख्य महंगाई यानी मुद्रास्फीति से होना चाहिए या सकल मुद्रास्फीति से। आरबीआई जानना चाहता है कि चार फीसदी का लक्ष्य अब भी वृद्धि और स्थिरता में संतुलन बनाने के लिए उपयुक्त है या नहीं। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने लक्ष्य के प्रति दो फीसदी घट-बढ़ वाली संतोषजनक स्थिति का दायरा बदले जाने और निर्धारित लक्ष्य को हटाकर सिर्फ एक दायरा ही रखे जाने पर लोगों से राय मांगी गई है। रिजर्व बैंक के चर्चा पत्र में कहा गया है, ''अब तक का अनुभव व्यापक रूप से सकारात्मक रहा है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की समीक्षा बैठक में खुदरा महंगाई के आंकड़ों को मुख्य तौर पर ध्यान में रखते हुए अपनी मौद्रिक नीति तय करती है। भारत ने वर्ष 2016 में सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति रूपरेखा समझौते के बाद लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्य प्रणाली को अपनाई थी। इसके तहत ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति को चार फीसदी पर रखने का लक्ष्य तय किया गया, जिसमें दो फीसदी घट-बढ़ की छूट दी गई थी। यह मौजूदा व्यवस्था 2026 तक लागू है। आरबीआई ने जारी बयान में कहा कि पिछले नौ वर्षों के अनुभव में शुरुआती तीन और हाल के तीन साल निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ही रहे। लेकिन बीच के वर्षों में कोरोना महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे झटकों के कारण महंगाई की दर ऊपरी दायरे के करीब रही।

सेबी प्रमुख ने प्री-आईपीओ कंपनियों के लिए विनियमित प्लेटफॉर्म शुरू करने का दिया संकेत

एजेंसी

मुंबई। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे ने कहा कि पूंजी बाजार नियामक एक विनियमित मंच पेश कर सकता है, जहां आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने वाली कंपनियां सूचीबद्ध होने से पहले कुछ खुलासे करने के बाद कारोबार कर सकेंगी। पूंजी बाजार नियामक सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे ने यहां फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के 22वें वार्षिक पूंजी बाजार सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। सेबी अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को भारत के पूंजी बाजारों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से व्यापक सुधारों के एक हिस्से के रूप में रेखांकित किया। तुहिन कांता पांडे ने कहा कि निवेशकों के लिए निवेश का निर्णय लेने के लिए अक्सर लिस्टिंग से पहले की जानकारी पर्याप्त नहीं होती। उन्होंने कहा कि यह पहल पायलट आधार पर होगी। पांडे ने कहा कि नियामक का मानना है कि अंतर्निहित इक्विटी बाजार को मज़बूत बनाने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सेबी का ये प्रस्ताव ऐसे समय में आया है, जब भारत के पूंजी बाजार तेजी से बढ़ रहा हैं, जिसमें 13 करोड़ विशिष्ट निवेशक और 7 करोड़ म्यूचुअल फंड निवेशक शामिल हैं, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा प्रतिभूति बाजार बन गया है। प्राथमिक बाजार से धन उगाहने का लक्ष्य वित्त वर्ष 2024-25 में 4.3 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच गया है, जबकि भविष्य के प्रस्तावों के लिए 1.4 ट्रिलियन रुपये की मजबूत पाइपलाइन की पहचान की गई है।

भारत से बाहर विस्तार की तैयारी में टाटा मोटर्स

नई दिल्ली। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्रा ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में हमारी वापसी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। भारतीय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर टाटा मोटर्स ने घोषणा की कि उसने छह साल बाद दक्षिण अफ्रीका के यात्री वाहन बाजार में फिर से प्रवेश किया है। कंपनी ने तीन एसयूवी और एक एंट्री-लेवल की कॉम्पैक्ट हैचबैक लॉन्च की है। टाटा मोटर्स ने दक्षिण अफ्रीकी बाजार में पंच (कॉम्पैक्ट एसयूवी), कर्व (कूप इंस्पायर्ड एसयूवी), टियागो (हैचबैक) और हैरियर (प्रीमियम एसयूवी) जैसे मॉडल लॉन्च किए हैं। ये सभी मॉडल पारंपरिक ईंधन (पेट्रोल-डीजल) पर आधारित हैं और सितंबर से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्रा ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में हमारी वापसी टाटा मोटर्स की वैश्विक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

हरित ऊर्जा को प्रतिबद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए मप्र बन रहा आकर्षण का केन्द्र : मुख्यमंत्री

एजेंसी

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा के प्रमुख केन्द्र के रूप में उभर रहा है। हरित ऊर्जा के लिए प्रतिबद्ध बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए मध्य प्रदेश आकर्षण का केन्द्र बन रहा है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां यहां अपनी निर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक हैं। उद्योगों के साथ कृषकों और जनसामान्य को सौर ऊर्जा व अन्य वैकल्पिक स्त्रोतों से किफायती दर पर विद्युत उपलब्ध कराने की दिशा में हो रहे शोध और नवाचारों को राज्य सरकार हरसंभव सहयोग और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह बात मध्य प्रदेश प्रवास पर आए सेक्का क्लाइमेट फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट क्ले स्ट्रेंजर और सीमा पॉल, यूनिवर्सिटी ऑफ़ केलिफोर्निया बर्कले के इंडिया एनर्जी एंड क्लाइमेट सेंटर (आईईसीसी) के सीनियर एडवाइजर मोहित भार्गव से भोपाल स्थित मंत्रालय में हुई सौजन्य भेंट के दौरान कही। बैठक में सहयोग के उद्देश्यों पर चर्चा के साथ स्वच्छ एवं सतत् भविष्य के लिए साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के सहयोग से मैनिट में 'सेंटर फॉर मिशन ऑन एनर्जी ट्रांजिशन' आरंभ

अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव ने बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के सहयोग से नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग और भोपाल के मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मैनिट) के बीच एमओयू हुआ है। इसके अंतर्गत मैनिट में 'सेंटर फॉर

मिशन ऑन एनर्जी ट्रांजिशन' (सीएमइटी) का शुभारंभ हुआ। यह केन्द्र भारत की भविष्य की ऊर्जा आवश्यकता के क्षेत्र में कार्य करेगा और अकादमिक-नीतिगत और औद्योगिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत आवश्यक सुझाव एवं रणनीतियां निर्धारित करने में सहयोग देगा। मैनिट भोपाल के निदेशक केके शुक्ला ने कहा कि कैलेफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले एवं ग्लोबल पार्टर्नर सेकोइया क्लाइमेट फाउंडेशन के सहयोग से प्रारंभ केन्द्र भारत में ऊर्जा परिवर्तन को गति देने के लिये अकादमिक नीति निर्माण तथा औद्योगिक क्षेत्रों के बीच उत्कृष्ट सहयोग को दर्शाती है। कार्यक्रम में ऊर्जा क्षेत्र की अग्रणी संस्थाएं जीआईज़ेड, सीईईडब्ल्यू, डब्ल्यूआरआई, सीएसआईएस और शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। ऊर्जा परिवर्तन मिशन केन्द्र के प्रारंभ होने से स्वच्छ एवं नवकरणीय ऊर्जा प्रणालियों पर उन्नत शोध किया जा सकेगा। नीति निर्माताओं को डेटा आधारित सुझाव एवं समाधान उपलब्ध कराये जा सकेंगे। ग्रिड स्थिरता, ऊर्जा भंडारण और डिमांड साइड प्रबंधन के लिए नवाचारों का विकास किया जा सकेगा। साथ ही प्रशिक्षण कार्यशालाओं और वैश्विक ज्ञान विनिमय के माध्यम से क्षमता निर्माण करने में भी मदद मिलेगी।मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अमन बीर सिंह बैंस ने बताया कि नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग और मैनिट के हुये एमओयू से मध्य प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा सकेगा।

बॉलीवुड छोड़कर कौन-कौन सा बिजनेस कर रही हैं

सना खान

जानें उनके बारे में

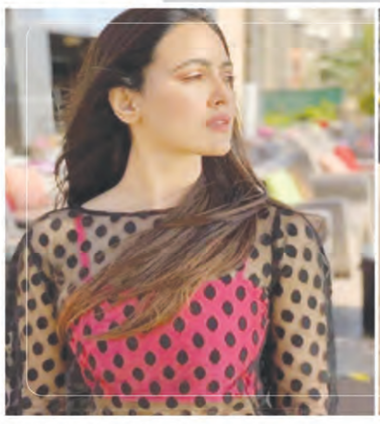

करण कुंद्रा अपने काम से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा सुर्खियां बटोरते रहते हैं. करण और टीवी एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश अपने रिलेशनशिप को लेकर हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं. लेकिन इसी बीच जब करण को लोगों ने डेटिंग एप पर देखा, तो सभी उनकी प्रोफाइल चेक करने लगे. कई लोगों ने डेटिंग ऐप बम्बल से उनकी प्रोफाइल की फोटो सोशल मीडिया पर भी शेयर की है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.वायरल स्क्रीनशॉट में करण बेज रंग की टी-शर्ट और जींस पहने हुए कैजुअल कपड़े पहने हुए हैं. उनकी उम्र भी 40 साल दिखाई गई है. इसने तुरंत फैन्स का ध्यान खींचा, क्योंकि एक्टर इस वक्त तेजस्वी के साथ रिश्ते में हैं. दिलचस्प बात यह है कि करण अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अनुषा दांडेकर के साथ रिश्ते के दौरान बम्बल के ब्रांड एंबेसडर के रूप में इससे जुड़े थे.

डेटिंग एप पर दिखे करण कुंद्रा

हालांकि अब फैन्स अपने अलग-अलग अंदाजे लगा रहे हैं. किसी का मानना है कि उनकी ये प्रोफाइल उनकी कमीटमेंट्स के चलते बनी होगी. वहीं, कुछ लोग इसे करण की हालिया एक्टिविटी बता रहे हैं. लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये प्रोफाइल नई है या पुरानी. रेडिट पर स्क्रीनशॉट सामने आने के बाद, कई सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाया कि तेजस्वी के लिए कमिटेड होते हुए भी करण डेटिंग ऐप पर कैसे हो सकते हैं, बाकी लोगों ने दावों को सिरे से खारिज कर दिया, यह सुझाव देते हुए कि छवियों में हेरफेर किया गया था.

फैन्स ने प्रोफाइल को बताया फेक

एक रेडिट यूजर ने लिखा कि फोटो साफतौर पर एडिटेड लग रही है, जबकि दूसरे ने दावा किया कि प्रोफ़ाइल फेक लग रही है. अभी तक करण ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है. उनकी और तेजस्वी की पॉपुलैरिटी और बड़े फैन बेस को देखते हुए, कथित डेटिंग ऐप प्रोफ़ाइल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है, और कई लोग एक्टर के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं.ये बात किसी से छिपी नहीं है कि करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश 2021 से रिलेशनशिप में हैं.

उनकी बॉडी कभी नहीं मिली... मां को याद कर भावुक हुई Pooja Bedi, 50 साल भी पूरे नहीं कर सकी थीं प्रोतिमा

बॉलीवुड एक्टर कबीर बेदी की बेटी पूजा बेदी अब लाइमलाइट से दूर रहती हैं. एक्ट्रेस ने अपने करियर में बॉलीवुड फिल्मों और टीवी सीरीज में काम किया है. लेकिन लंबे वक्त से वे स्क्रीन पर नजर नहीं आई हैं. हालांकि वे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और 55 साल की उम्र में अपनी फिटनेस और फैशन सेंस से सभी को धोखा दे जाती हैं. हाल ही में पूजा बेदी ने अपनी मां को याद किया है. एक्ट्रेस की मां और कबीर बेदी की पहली पत्नी प्रोतिमा बेदी मशहूर मॉडल और डांसर थीं. पूजा अपनी मां को याद करते हुए भावुक नजर आईं और उन्होंने बताया कि आखिर कैसे उनकी मां का निधन हुआ था और वे कभी भी वापिस नहीं आईं.

पूजा बेदी ने क्या कहा ?

एक्ट्रेस पूजा बेदी ने अपनी मां को याद करते हुए कहा- मुझे अपनी मां को लेकर कई सारे अफसोस हैं जो 50 साल से कम उम्र में ही दुनिया छोड़कर चली गई थीं. बहुत कुछ ऐसा था जो मैं उनके साथ करना चाहती थी. लेकिन वो एक ऐसी महिला थीं जो अपना जीवन अपनी ही शर्तों पर जीना चाहती थी. वे अपनी शर्तों पर जीना भी चाहती थीं और अपनी ही शर्तों पर वे मरना भी चाहती थीं. वे ऐसी थीं जो कुदरत के करीब रहना चाहती थीं और कुदरत की गोद में समा गईं.

आगे पूजा ने कहा- वे अपने जीवन के अंत में ऐसा नहीं चाहती थीं कि उन्हें दफनाया जाए या फिर जलाया जाए. वे कुदरत के नजारों के बीच मरना चाहती थीं. वहीं उनका ग्रैंड फिनाले था. और ऐसा ही कुछ उन्होंने किया भी. उनकी डेड बॉडी कभी नहीं मिली. इस पूरी पृथ्वी पर इस पूरे ब्रह्मांड में वे अपने आप में अविश्वसनीय उर्जा से भरी हुई थीं. इसके बाद पूजा ने कहा कि उनकी मां जब आखिरी बार उनसे मिलीं तो उन्होंने अपने सारे डॉक्युमेंट्स प्रॉपर्टी पेपर्स और आभूषण उन्हें थमा दिए और उनसे जाने की इजाजत मांगी.

कबीर बेदी ने की 4 शादियां

प्रोतिमा बेदी की बात करें तो उन्होंने कबीर बेदी से साल 1969 में शादी की थी और साल 1974 में दोनों का तलाक हो गया था. दोनों की शादी 5 साल तक चली थी. इसके बाद कबीर बेदी ने 3 और शादियां की. उन्होंने चौथी शादी परवीन दुसांज बेदी से साल 2016 में की थी. इस दौरान एक्टर की उम्र 70 साल की थी. परवीन उनसे उम्र में 30 साल छोटी हैं.

फिर एक्शन को तैयार सनी देओल, फिल्म में होगी 49 साल छोटी एक्ट्रेस?

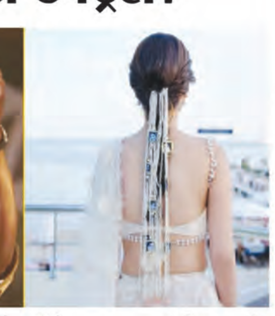

सनी पाजी अब असली धमाल मचाने लौट रहे हैं. इस साल उनकी एक बड़ी फिल्म रिलीज हो चुकी है. वहीं साल के एंड में सफर को रिलीज करने की भी प्लानिंग है. कुछ दिनों पहले उन्हें एक बड़ी एक्शन फिल्म मिलने की खबर सामने आई थी. अब नए अपडेट के मुताबिक, पिक्चर में एक एक्ट्रेस की एंट्री हुई है. जो सनी देओल से 49 साल छोटी हैं.

बॉलीवुड के एक्शन किंग सनी देओल की इस वक्त दो बड़ी फिल्मों का इंतजार हो रहा है. जिसमें एक है- लाहौर 1947, जो रिलीज को लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं है. वहीं दूसरी 'बॉर्डर 2' है, जो अगले साल आएगी और काम कंप्लीट किया जा चुका है. यूं तो उन्हें एक के बाद एक बड़ी फिल्में ऑफर हो रही हैं. जिसमें एक बड़ी एक्शन फिल्म शामिल है. कहा गया है कि इसे Siddharth P Malhotra बना रहे हैं. अब पिक्चर में 18 साल की एक्ट्रेस की एंट्री हो गई है.इसी बीच बॉलीवुड हंगामा पर एक रिपोर्ट छपी. सोर्स के मुताबिक, लापता लेडीज से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस से सनी देओल की फिल्म के लिए बात चल रही है. यह एक एक्शन फिल्म है, जिसका टाइटल अबतक कंफर्म नहीं किया गया है. हालांकि, यह सब शुरू कैसे हुआ ? जानिए.

सनी देओल की फिल्म में होगी ये एक्ट्रेस ?

दरअसल कुछ हफ्तों पहले नितांशी गोयल को सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के ऑफिस में देखा गया था. जिसके बाद से ही उनकी कास्टिंग को लेकर खबरें सामने आ रही हैं. हालांकि, मेकर्स के ऑफिशियल ऐलान का इंतजार है. पर कहा जा रहा है कि नितांशी गोयल को सनी देओल के साथ फिल्म में लिया जाएगा. इस फिल्म को Suparn Verma लिख रहे हैं, जो 2007 की हॉलीवुड थ्रिलर Death Sentence से इंस्पायर्ड होगी. इसी साल फिल्म को फ्लोर पर लाया जाएगा.

हालांकि, 'लापता लेडीज' में नितांशी गोयल ने अपनी एक्टिंग से हर किसी को काफी इम्प्रेस किया था. वहीं सोशल मीडिया के जरिए अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. उनके अगले प्रोजेक्ट का फैन्स को बेसब्री से इंतजार है. देखना होगा फिल्म को लेकर मेकर्स कब टीम अनाउंस करते हैं. लेकिन वो फिल्म में होंगी, तो यह हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर में कुछ नया एंगल जोड़ेगा.

सनी देओल से कितनी छोटी हैं ?

सनी देओल 67 साल के हैं. जबकि, नितांशी गोयल 18 साल की है. यानी दोनों के बीच 49 साल का एज गैप है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नितांशी को किस रोल के लिए चुना जाता है. क्योंकि कपल तो नहीं होंगे, पर मेकर्स क्या प्लान करते हैं, देखना होगा. नितांशी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. उन्हें इंस्टाग्राम पर 10.6 मिलियन लोग फॉलो करते हैं.

अमीषा पटेल

की एक 'न'... 'तेरे नाम' की ये एक्ट्रेस बन गई स्टार

बॉलीवुड की बेस्ट रोमांटिक फिल्मों में एक 'तेरे नाम' है, जिसका एंड हर किसी को रुला जाता है. फिल्म तेरे नाम सलमान खान की बेहतरीन फिल्मों में एक है और इसी फिल्म से साउथ एक्ट्रेस भूमिका चावला ने भी डेब्यू किया था. फिल्म तेरे नाम में भूमिका ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और उन्हें लोगों ने खूब पसंद भी किया था. फिल्म में भूमिका ने निर्जरा भारद्वाज का रोल प्ले किया था. कम ही लोग ये बात जानते हैं कि ये रोल पहले 'गदर' एक्ट्रेस अमीषा पटेल को ऑफर हुआ था.

जी हां, आईएमडीबी के अनुसार, फिल्म तेरे नाम में लीड एक्ट्रेस निर्जरा का रोल अमीषा पटेल को ऑफर किया गया था लेकिन उस समय उन्हें डेट्स की प्रोबलम थी. दरअसल 2000 में फिल्म 'कहो ना प्यार है' और 2001 में फिल्म 'गदर- एक प्रेम कथा' जैसी दो ब्लॉकबस्टर देने के बाद अमीषा पटेल के पास बैक-टू-बैक फिल्मों के ऑफर थे. इसलिए उन्होंने फिल्म तेरे नाम करने से मना कर दिया और ये फिल्म भूमिका चावला को मिल गई.

फिल्म 'तेरे नाम' ने कितनी कमाई की थी ?

15 अगस्त 2003 को रिलीज हुई फिल्म तेरे नाम के डायरेक्टर सतीश कौशिक थे. फिल्म में 'तेरे नाम', 'ओढ़नी', 'लगन लगी', 'तुमसे मिलना', 'ओ जाना', 'तूने साथ जो मेरा छोड़ा' जैसे गाने आज भी पसंद किए जाते हैं. फिल्म में सलमान खान और भूमिका चावला लीड रोल में थे.

वहीं रवि किशन, सविता प्रभूने, महेंद्र वर्मा, सचिन खेडकर, अनंग देसाई और सरफराज खान जैसे कलाकारों ने भी अहम किरदार निभाए थे. ये फिल्म आप जी5 पर फ्री में देख सकते हैं. वहीं अगर कमाई की बात करें तो Sacnilk के मुताबिक, फिल्म तेरे नाम का बजट 12 करोड़ था जबकि इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 24.55 करोड़ का था.

भूमिका चावला कौन हैं ?

21 अगस्त 1978 को दिल्ली में जन्मीं भूमिका चावला पंजाबी हैं. मगर उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत तेलुगू फिल्म Yuvakudu (2000) से की थी, इसके बाद उन्होंने तमिल फिल्म बद्री (2001) की थी.

बॉलीवुड में भूमिका चावला की पहली फिल्म तेरे नाम थी जो सफल हुई. इस फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवॉर्ड उन्हें मिला था. फिल्म तेरे नाम के बाद भूमिका ने 'रन', 'दिल ने जिसे अपना कहा', 'सिलसिले' जैसी फिल्में कीं. भूमिका ने अपने करियर में हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगू और पंजाबी भाषाओं की फिल्मों में काम किया है.

रेकी हीलर्स के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं दीक्षांत समारोह आयोजित

दिव्य दिल्ली : दिल्ली के द्वारका स्थित राही वेलनेस सेंटर में विश्वविख्यात रेकी एंड एस्ट्रो हीलिंग इंस्टीट्यूट (राही इंस्टीट्यूट) द्वारा रेकी हीलर्स के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर 10 से अधिक रेकी एडवांस हीलर्स, रेकी मास्टर्स एवं पास्ट लाइफ हीलर्स को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने अपने जीवन में आए आध्यात्मिक परिवर्तनों और उपचार के अनुभव साझा किए तथा राही इंस्टीट्यूट के संस्थापक व संचालक गुरुजी डॉ. उमाकांत शर्मा की शिक्षण प्रणाली व आध्यात्मिक व्यक्तित्व की सराहना की। राही इंस्टीट्यूट पिछले 20 वर्षों से विश्वभर में 50 से अधिक आध्यात्मिक और परंपरागत उपचार पद्धतियों पर कार्यरत है। कार्यक्रम में डॉ. प्रकाशी शर्मा, डॉ. अलका प्रियदर्शिनी, रेकी मास्टर तुषार वर्मा, रेकी मास्टर देवजानी भट्टाचार्य, आचार्य पूजा रहेजा, टैरो विशेषज्ञ तरूना कामरा, एडवांस हीलर रजनी, शिल्पा एवं रेकी हीलर युक्ता समेत कई विद्वान शामिल हुए। राही इंस्टीट्यूट ने सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य और आध्यात्मिक सफलता की शुभकामनाएँ दीं।

गंगा में नाव संचालन बंद होने से नाविकों के लिए आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया - प्रमोद मांझी

वाराणसी। मां गंगा निषादराज सेवा न्यास के अध्यक्ष प्रमोद मांझी ने कहा कि गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद से अभी तक गंगा नदी में नाव का संचालन बंद है। इससे नाव के दम पर परिवार चलाने वाले नाविकों के लिए आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। और ज्यादा दिन तक हम अपनी नावों का संचालन नहीं रोक सकते हैं।

वाराणसी के नाविकों ने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि 41 दिन पहले से बंद नावों के संचालन को खोलने की अनुमति दी जाए। नाविकों के परिवार में दोनों समय का चूल्हा जल सके। वाराणसी आने वाले पर्यटक गंगा में नाव विहार कर सके, जिससे उनकी रोजी रोटी चले। प्रशासन को शीघ्रता से निर्णय लेना चाहिए, जिससे नाविक परिवार के सदस्यों का भरण पोषण हो सके।

प्रमोद मांझी ने कहा कि इससे पहले पुलिस उपायुक्त गौरव वंसवाल को नाविकों की तरफ से पत्रक सौंपा गया है और सुरक्षित नाव संचालन की अनुमति मांगी गई है। पत्रक सौंपने वाले नाविकों में राकेश, पप्पू, विकास, अजीत, शंभु मुख्य रूप से मौजूद रहे।

महिला को ई रिक्शा ने मारी टक्टर महिला की मौत

कौशांबी। मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के कोतारी पश्चिम गांव में शुक्रवार की सुबह साढ़े 6 बजे सड़क हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है दुर्घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे मामले की सूचना पुलिस को दी गई है मौके पर पहुंची पुलिस में महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है दुर्घटना करने वाला चालक वाहन को छोड़कर फरार हो गया है।

जानकारी के मुताबिक मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के कोतारी पश्चिम निवासी बच्ची देवी उम्र 50 वर्ष पत्नी बच्चा सरोज रोज की तरह सुबह शौच के लिए खेत की ओर जा रही थीं। तभी करारी की ओर से तेज रफ्तार में आ रहा एक बैटरी ई-रिक्शा करारी-मंझनपुर मुख्य मार्ग पर पहुँचा और उसने महिला को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बच्ची देवी गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गईं और कुछ ही मिनटों में उनकी मौके पर तड़प तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई। हादसे को देख स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और दुर्घटना की थाना पुलिस को सूचना दी सूचना मिलते ही मंझनपुर थाना पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुँची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अचानक हुए इस हादसे से गांव में मातम का माहौल है। मृतका के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हैं।

व्यापारी संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित

दिव्य दिल्ली : दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन ने अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में व्यापारी संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर DDCA अध्यक्ष रोहन जेटली, सी.के. खन्ना, अशोक शर्मा, शिखा कुमार, नवदीप मल्होत्रा, कुंज नाकरा, राजेश खन्ना और राहुल अदलखा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि इस समय दिल्ली प्रीमियर लीग टूनामेंट चल रहा है और इसके अधिक प्रचार-प्रसार के लिए सीटीआई से जुड़ी 60 प्रसिद्ध सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को आमंत्रित कर सम्मानित किया गया। इनमें प्रियंका सक्सेना, मीन्स मल्होत्रा, प्रियंका राजपाल, रिचा मेहता, श्वेता राजपाल, अंजलि मठारू, कंचन प्रभा, मुस्कान मोहन, रश्मि छाबड़ा, निधि नंदराजोग, भक्ति दूबे, उपाली छाबड़ा, आशी बजाज, साइमा शेख, तनीषा कालरा, सुधा बब्बर, सुजाता सिंह और मधु तलवार समेत कई प्रमुख नाम शामिल रहे। बृजेश गोयल ने आगे बताया कि सीटीआई अब व्यापारियों के लिए भी टूर्नामेंट आयोजित करने जा रहा है, जिसमें क्रिकेट और बैडमिंटन जैसे खेल शामिल होंगे। इसका उद्देश्य व्यापारियों में खेलों के प्रति जागरूकता और रुचि बढ़ाना है।

मंत्री सुरेश खन्ना ने वाराणसी के जयप्रकाश नगर में किया स्थलीय निरीक्षण, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

वाराणसी। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने शनिवार को वाराणसी के जयप्रकाश नगर में मलिन बस्ती सहित कालोनी में साफ सफाई का स्थलीय निरीक्षण किया। वाराणसी कैंट क्षेत्र में जयप्रकाश नगर में स्वच्छता कार्यों से मंत्री सुरेश खन्ना बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं दिखे, उन्होंने वहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए नगर निगम के अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देशित किया। साथ ही स्थानीय विधायक सौरभ श्रीवास्तव से क्षेत्र में निरंतर निगरानी के लिए भी कहा।

प्रभार जनपद वाराणसी में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने शहर की साफ सफाई पर जोर देते हुए नगर निगम के अधिकारियों से कहा कि सीवर की समय से सफाई होनी चाहिए। बंद नालियों को खोलिए और जलभराव होने से रोकने का प्रयास कीजिए। कूड़े के ढेर को लगने से रोकिए। अधिकारी स्वयं सड़क पर उतर कर हर क्षेत्र की स्वच्छता जाने और आवश्यक दिशा निर्देश दे।

इस निरीक्षण के उपरांत मंत्री सुरेश खन्ना वाराणसी के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में चले गए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सुरेश खन्ना ने वहां भी अधिकारियों को सख्त लहजे सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। बैठक में महापौर अशोक तिवारी, विधायकों सहित अधिकारीगण मौजूद रहे।

प्रयागराज में एक अन्य मुठभेड़ के बीच पच्चीस हजार का इनामी गोली लगने से घायल

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित करेली थाना क्षेत्र में शुक्रवार की देर रात हुई मुठभेड़ में एक पच्चीस हजार का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस टीम ने घायल बदमाश को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है।

सहायक पुलिस आयुक्त अतरसुइया राजकुमार मीना ने बताया कि गोली से घायल बदमाश की पहचान झारखण्ड के साहेबगंज जनपद के राजमहल थाना क्षेत्र में स्थित मजहर टोला निवासी आजाद उर्फ बिल्ली पुत्र स्वर्गीय अनीश अहमद जो वर्तमान में झुग्गी झोपड़ी बारह मार्केट थाना करैली में रहता है,के रूप में हुई है। उसे तत्काल उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ?अभियान के तहत करेली थाने की पुलिस टीम बक्सीमोड़ा बैरियर पर शुक्रवार की रात संदिग्ध वाहनों की चेकिंग दौरान एक संदिग्ध मोटर साइकिल सवार आता हुआ दिखाई दिया तो पुलिस टीम ने रोकने का इशारा किया। लेकिन वह भागते हुए पुलिस टीम पर असलहे से फायरिंग करने लगा। पुलिस टीम ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया।

सिद्धार्थ और जान्हवी ने फिल्म परम सुंदरी की सफलता के लिए बंगला साहिब गुरुद्वारे में माथा टेका

दिव्य दिल्ली : दिल्ली में प्यार, ऊर्जा और जश्न का अनोखा नजारा देखने को मिला, जब सिद्धार्थ मल्होत्रा और जान्हवी कपूर अपनी आगामी फिल्म परम सुंदरी के प्रचार के लिए राजधानी पहुँचे। दोनों सितारों ने सबसे पहले बंगला साहिब गुरुद्वारे में माथा टेका और दिव्य आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के असली छोले-भटूरे और इंडिया गेट पर कैंडी फ्लॉस का मजा लेकर दिल्ली की रौनक का पूरा आनंद उठाया। शाम के समय सिद्धार्थ और जान्हवी ने राजधानी के प्रतिष्ठित थिएटर में ढोल-नगाड़ों के बीच पंजाबी अंदाज में एंट्री की और परदेसिया व चार्टबस्टर गाना डेंजर पर जबरदस्त परफॉर्मेंस देकर दर्शकों को दीवाना बना दिया। प्यार, हंसी और मस्ती से भरी इस शाम ने दिल्ली की आत्मा को कैद कर लिया और दर्शक लगातार तालियों से सितारों का हौसला बढ़ाते रहे। प्रशंसकों का दिल जीतने के बाद अब दिनेश विजान की मैडॉक फिल्म्स की फिल्म परम सुंदरी 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।

नाबालिक के साथ दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

प्रयागराज। डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र यादव के निर्देश पर घूरपुर पुलिस थाना क्षेत्र के एक गांव क नाबालिक किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में वांछित चल रहे एक आरोपी को शुक्रवार गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक घूरपुर दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि 23 जुलाई को एक नाबालिक किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त लवकुश उर्फ श्रीकांत पुत्र स्व0 रामचन्द्र निवासी ग्राम नेवादा नरैना थाना करछना जनपद प्रयागराज को मेवा लाल की बगिया तिराहा थाना नैनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया ।

नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी ।

दिल्ली की रामलीला कमेटी को आर्थिक सहयोग दिया जाए: अर्जुन कुमार

दिव्य दिल्ली : श्री रामलीला महासंघ के अध्यक्ष श्री अर्जुन कुमार ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना एवं दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर मांग की है कि हज एवं कावड़ की तर्ज पर दिल्ली की रामलीला कमेटी को निशुल्क बिजली, मोबाइल टॉयलेट, आर्थिक सहयोग दिया जाऐ श्री अर्जुन कुमार ने यह भी बताया कि मुगल काल से दिल्ली की रामलीलाओं को सभी सुविधा निशुल्क मिलती रही हैं, आज भी रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली रामलीला को दिल्ली नगर निगम बिजली, पानी अन्य सभी सुविधा निशुल्क उपलब्ध कराता है प्रभु श्री राम की लीलाओं में बहुत आस्था है, जो सदियों से चली आ रही है न केवल दिल्ली पूरे विश्व के अंदर रामलीलाओं का मंचन किया जाता है रामलीलाए हमारी सांस्कृतिक विरासत हैं, इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत हैं श्री रामलीला महासंघ के महामंत्री श्री सुभाष गोयल ने बताया कि रामलीला मंचन समारोह 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक मनाया जाएगा, दशहरा पर 2 अक्टूबर को पूरे देश में संपन्न होगो प्रभु श्री राम की रामलीला पूरे उत्साह से भव्य होगी।

रामलीला केवल श्रद्धा का विषय नहीं, बल्कि यह एक ऐसी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर है जो मयार्दा, भाईचारा, प्रेम, सौहार्द और एकता के देती हैं, रामलीला के मंचन से लोग प्रभु राम के आदर्श जीवन से प्रेरणा लेते हैं और अपने बच्चों को भी उत्तम संस्कार प्रदान करते हैं। सरकार सहयोग देगी, तो आने वाले समय में प्रभु राम के आदर्शों का प्रचार-प्रसार और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा, जिससे समाज में प्रेम, भाईचारे और सौहार्द का वातावरण और मजबूत होगा।

आजमगढ़ में एसटीएफ ने मुठभेड़ में एक लाख के ईनामी को किया ढेर

आजमगढ़। जिले के जहानगंज थाना क्षेत्र के सिंहपुर के गांव के समीप शुक्रवार को तड़के एसटीएफ वाराणसी इकाई और पुलिस को बड़ी सफलता मिली। लूट और हत्या के अभियोग में वांछित तथा एक लाख रुपये का ईनामी शातिर अपराधी शंकर कनौजिया पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया।

शुक्रवार की रात को एसटीएफ को जानकारी मिली कि शंकर कनौजिया अपने गिरोह के साथ आजमगढ़ क्षेत्र में किसी वारदात की योजना बना रहा है। निरीक्षक पुनीत सिंह परिहार के नेतृत्व में टीम ने उसे जहानगंज थाना क्षेत्र में घेरने का प्रयास किया। गिरफ्तारी के दौरान शंकर कनौजिया ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी, हालांकि पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए। आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। तत्काल उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके से पुलिस ने 9 एमएम कारबाइन, 9 एमएम पिस्टल, एक खुखरी और भारी मात्रा में जिंदा व खोखा कारतूस बरामद किये हैं।

गौरतलब है कि शंकर कनौजिया वर्ष 2011 में दोहरीघाट क्षेत्र में लूट के दौरान विंध्याचल पांडे की हत्या कर फरार हो गया था। इसके बाद से वह लगातार आपराधिक वारदातों में शामिल रहा। जुलाई 2024 में उसने महाराजगंज निवासी शैलेंद्र सिंह का अपहरण कर लोडर गाड़ी लूट ली थी और हत्या के बाद उनका धड़ से सिर अलग कर दिया था। इसी घटना के बाद उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

झपटमार कर गहने छीनने वाला शातिर गिरफ्तार

प्रयागराज। मऊआइमा थाने की पुलिस ने झपटमार करने वाले एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से लूट व चोरी के गहने व मोबाइल फोन बरामद किया है। पकड़ा गया अभियुक्त आदर्श विश्वकर्मा निवासी ग्राम फरीदपुर थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज है।मऊआइमा पुलिस ने इसे मऊआइमा क्षेत्र के हरखपुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार अभियुक्त साथियों के साथ मिलकर 28 जून को मऊआइमा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम महरौड़ा में श्याम कुमार सोनी की बैग में रखा चांदी के पायल को झपट्टा मारकर छीन लिया। इसके अलावा 22 जुलाई को थाना मऊआइमा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम उधोपुर खगरिया में सुनील कुमार सोनी का मोटरसाइकिल पर टंगा बैग झपट्टा मारकर छीन लिया था। इसमें सोने चांदी के आभूषण थे।

सात सौ किलोमीटर दूर किया जूनियर इंजीनियर का ट्रांसफर, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

-पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम से पश्चिमांचल भेजा

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जूनियर इंजीनियर अविनाश कुमार का 700 किलोमीटर दूर ट्रांसफर करने के आदेश पर छह सप्ताह के लिए रोक लगा दी है। जूनियर इंजीनियर अविनाश कुमार की याचिका पर न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने यह आदेश पारित किया है।

अविनाश कुमार को पूर्व में कुछ आरोपों के आधार पर निलम्बित किया गया था, जिन्हें बाद में वापस ले लिया गया। इसके बावजूद उनका स्थानांतरण पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कर दिया गया, जो उनके मूल स्थान से करीब 700 किलोमीटर दूर है।

फर्जी आयुष्मान का लाभ उठाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई : सांसद

स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के उत्पाद बिकेंगे अमेजन-फ्लिपकार्ट पर

झांसी। झांसी-ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित हुई। बैठक में घंटों चली विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए सांसद ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सरकार की मंशा गरीबों तक सीधा लाभ पहुँचाने की है, ऐसे में योजनाओं का लाभ किसी भी पात्र व्यक्ति से वंचित न हो। सांसद ने कहा कि अधिकारी अपने विभागीय कार्यों व लक्ष्यों की जानकारी जनप्रतिनिधियों को अवश्य उपलब्ध कराएं, ताकि योजनाओं का समयबद्ध सत्यापन और क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि योजनाओं में अनावश्यक देरी किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सांसद ने कहा कि जिले में मनरेगा के तहत वर्ष 2025-26 में 9 हजार श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का रोस्टर जारी करते हुए पात्र लाभार्थियों का चयन शीघ्र करने के निर्देश दिए। एनएचएआई के कार्यों की समीक्षा करते हुए सांसद ने कहा कि सड़कों पर गड्ढे और छुट्टा गोवंश दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। उन्होंने तत्काल मरम्मत, अवैध कट बंद करने और सड़क सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम ने कैटल कैचर की व्यवस्था करने का सुझाव दिया। बिजली व्यवस्था पर जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई। सांसद ने सब स्टेशन निर्माण और क्षमता वृद्धि की सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने को कहा। जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए सांसद ने कहा कि अब तक 10 में से 7 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, शेष कार्य जल्द पूरा कराया जाए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि हर घर पेयजल योजना में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी। पाइपलाइन डालने के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त कर आवागमन योग्य बनाने के निर्देश दिए। बैठक में एमएलसी रामतीर्थ सिंघल ने ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि, विधायक प्रतिनिधि दीपक कठैल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की गंदगी व निजी अस्पतालों में दलाली का मुद्दा उठाया। एमएलसी रमा निरंजन ने नए मकानों में बिजली कनेक्शन में हो रही देरी पर सवाल खड़े किए। शिक्षक विधायक बाबूलाल तिवारी ने लगातार कटौती पर नाराजगी जताई। जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने कहा कि बैठक में दिए गए सभी दिशा-निर्देशों और सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक का संचालन सीडीओ जुनैद अहमद ने

Published, printed and owned by Rajesh.Chauhan, printed at B B Graphic printer Z--57 Okhla Industrial Area ph.2 New Delhi -110020 and published at BG 6 305 B Paschim Vihar New Delhi --110063 Editor Rajesh.Chauhan. E mail ID-rajeshchauhan4569@gmail.com, Contact No. - 9873104569, RNI No DELENG/2013/54397